



जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं आरएसएस

शर्त यह कि इसका इस्तेमाल चुनावी उद्देश्यों के लिए न हो

पलक्कड़ (केरल)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की ओर से जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। संघ ने जाति जनगणना के लिए अपना समर्थन जताया है, मगर कुछ शर्तें भी रखी हैं। केरल के पलक्कड़ में तीन दिन तक चली समन्वय बैठक के समापन के बाद आरएसएस के मुख्य प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने सवालों के जवाब दिए। जातिगत जनगणना के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि जन कल्याण के लिए यह उपयोगी है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि इसका इस्तेमाल चुनावी उद्देश्यों के लिए न हो सुनील आंबेकर ने कहा, हमारे समाज में जाति संवेदनशील मुद्दा है। यह देश की एकता से भी जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, न कि चुनाव और राजनीति को ध्यान में रखकर। सरकार को डेटा की जरूरत पड़ती है। समाज की कुछ जाति के लोगों के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इन उद्देश्यों के लिए इसे (जाति जनगणना) करवाना चाहिए। जाति जनगणना के सवाल पर उन्होंने अगे कहा कि लोक कल्याण के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसे पॉलिटिकल टूल



बनने से रोकना होगा। अत्याचार से पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय की जरूरत संघ की मीटिंग में पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई जघन्य घटना की निंदा की गई और इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। अत्याचार से पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए कानूनों और दंडनीय कार्रवाइयों पर फिर से विचार करने की जरूरत पर बल दिया गया। आंबेकर ने कहा कि बैठक में मौजूद रहे लोगों का मानना है कि इन सभी पर दोबारा विचार करने की जरूरत है ताकि हमारे पास उचित प्रक्रिया, फास्ट-ट्रैक प्रक्रियाएं उपलब्ध हों और हम पीड़ित के लिए न्याय सुनिश्चित कर सकें। नड्डा के बयान को बताया

पारिवारिक मामला जेपी नड्डा के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी बड़ी हो गई हैं उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं हैं, इस पर सुनील आंबेकर ने कहा कि हमारे मिशन के बारे में मूल विचार सभी के लिए बहुत स्पष्ट है, अन्य मुद्दों को हल किया जाएगा, यह एक पारिवारिक मामला है। इसे हल किया जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि शुरू में हम अक्षम होंगे। थोड़ा कम होंगे। तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आज भाजपा सक्षम है, आज पार्टी अपने आप को चला रही है। नड्डा के इस बयान से काफी हंगाम मचा था।

भारत को पैरालंपिक में दूसरा गोल्ड, बैडमिंटन खिलाड़ी ने किया कमाल

नितेश कुमार ने पेरिस में

लहराया तिरंगा

पेरिस। पैरालंपिक 2024 में भारत के खाते में दूसरा गोल्ड मेडल आ गया है। बैडमिंटन में नितेश कुमार ने भारत के लिए यह गोल्ड जीता। पुरुष सिंगल्स के एसएल3 कैटेगरी में 29 साल के नितेश ने ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को 21-14, 18-21, 23-21 से हराया। 29 साल के भारतीय खिलाड़ी का यह पहला ओलंपिक मेडल है। इस पैरालंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल शूटिंग में अविन लेखरा ने जीता था। राजस्थान में जन्मे नितेश कुमार ने पहले गेम को आसानी से अपने नाम कर लिया। दूसरे गेम में भी वे आगे चल रहे थे। हालांकि फिर वापसी करते हुए बेथेल ने जीत हासिल की। इस तरह मुक़ाबला तीसरे गेम में पहुंचा। बेथेल को मैच पॉइंट भी मिला। हालांकि नितेश ने उन्हें सफल नहीं होने दिया और गेम को 23-21 से जीतकर भारत की झोली



में गोल्ड मेडल डाल दिया। नितेश कुमार को इसी साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ता था। वहां सेमीफाइनल में नितेश बेथेल से ही हार गए थे। लेकिन अब पैरालंपिक के फाइनल में बेथेल को हराकर नितेश ने अपना बदला पूरा किया। 2022 में 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में नितेश ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। पिछले साल एशियन पैरा गेम्स में पुरुष डबल्स में उन्हें गोल्ड मिला था जबकि सिंगल्स में सिल्वर से संतोष करना पड़ा था। ट्रेन दुर्घटना में गंवा दिया था पैर नितेश एक इंजीनियर हैं, जिनका कॉलेज के दौरान एक ट्रेन दुर्घटना

में जीवन बदल गया, वे अपना पांव गंवा चुके थे। इसके परिणामस्वरूप उनके बाएं पैर की जगह कुत्रिम पैर लगा दिया गया। छह फीट लंबे नितेश ने कोर्ट पर एक शानदार रिवर्स ड्रॉप शॉट विकसित किया है। पेरिस जाने से पहले उन्होंने छह सप्ताह तक पुलेला गोपीचंद अकादमी में गहन प्रशिक्षण लिया, जिसमें उन्होंने विशिष्ट कौशल पर ध्यान केंद्रित किया। भारत के हुए कुल 9 मेडल पेरिस पैरालंपिक में भारत के कुल 9 मेडल हो गए हैं। दो गोल्ड के अलावा भारतीय पैराएथलीट्स ने 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल पर भी कब्जा जमाया है। पैरालंपिक में भारत ने अपना बेस्ट प्रदर्शन तोक्यो 2020 में किया था। तब देश के आते में 5 गोल्ड के साथ ही 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज आए थे। इस बार उम्मीद कि जा रही है कि भारत तोक्यो से भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 20 से ज्यादा मेडल पर कब्जा करेगा।

विवाद की सीरीज: वेब सीरीज ‘आईसी 814: द कंधार हाईजैक’ में आतंकीयों के हिंदू नाम पर गुस्सा

‘कंधार हाईजैक’ को लेकर नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को सरकार ने किया तलब

नई दिल्ली। साल 1999 के कंधार हाईजैक पर बनी वेब सीरीज ‘आईसी 814: द कंधार हाईजैक’ पिछले महीने 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है, जो रिलीज के बाद से ही विवादों में बुरी तरह से घिर चुकी है। लोग सोशल मीडिया पर इसके बायकॉट की मांग कर रहे हैं। दरअसल, सीरीज में प्लेन हाईजैक करने वाले आतंकीयों के नाम हिंदू दिखाए गए हैं, जिसको लेकर यह सारा विरोध उठ रहा है। साथ ही लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोगों में बढ़ती नाराजगी को देखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को तलब किया है। मंत्रालय ने उन्हें मंगलवार को पेश होने के लिए कहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बारे में गुस्सा जताया है कि आतंकीयों के नाम हिंदू क्यों रखे गए? एयर इंडिया का विमान आईसी 814 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से उड़ान भरने के बाद आतंकीयों द्वारा अगवा कर लिया गया था। पांच आतंकीयों ने विमान को हाईजैक किया था और ये सभी आतंकी मुस्लिम थे। सीरीज में दिखाए गए मुस्लिम आतंकीयों



के हिंदू नाम विमान को अगवा करने वाले आतंकीयों के असली नाम इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सन्नी अहमद, जहूर मिस्त्री और शाकिर थे। लेकिन अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी इस सीरीज में सभी आतंकीयों के नाम बदल दिए गए हैं। सीरीज में आतंकीयों के नाम भोला और शंकर बताए गए हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर विवाद उठ रहा है। साथ ही लोग सीरीज के बायकॉट की मांग कर रहे हैं। इस विमान ने कंधार उतरने से पहले कई जगहों पर रुकावटें झेली। इसमें 176 यात्री

थे। जैसे ही प्लेन भारतीय वायु क्षेत्र में घुसा, पांच नकाबपोश आतंकीयों ने इसे हाईजैक कर लिया। सच्ची घटना पर आधारित है सीरीज यह सीरीज सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि कंधार पहुंचने से पहले, आईसी 814 को अमृतसर, लाहौर, और दुबई में उतरना पड़ा। दुबई में आतंकीयों ने 27 यात्रियों महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को छोड़ दिया। एक यात्री को चाकू से गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हो गई।

भोपाल में निलंबित रजिस्ट्रार के घर एक का छापा, करोड़ों के घोटाले का है आरोप

भोपाल। राजधानी भोपाल में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। मामला भोपाल की राजीव गांधी प्रौद्योगिक विस्वविद्यालय (आरजीपीवी) में सरकारी राशि की हेराफेरी का है। ईडी की टीम ने निलंबित रजिस्ट्रार आरएस राजपूत के घर पर छापा मारा। सूत्रों के अनुसार, छापेमारी में घर से दस्तावेज और साक्ष्य ईडी की टीम ने बरामद किये हैं। बता दें कि रजिस्ट्रार आरएस राजपूत के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी से मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने छापेमारी को अंजाम दिया। आरोप है कि आरएस राजपूत के रजिस्ट्रार रहते आरजीपीवी में 19.48 करोड़ का घोटाला हुआ है। आरएस राजपूत पर सरकारी राशि को प्राइवेट खातों में ट्रांसफर करने का आरोप है। घोटाले में कुलपति की भी भूमिका बताई गई है।

मप्र हाईकोर्ट ने फिल्म इमरजेंसी पर सेंसर बोर्ड से मांगा जवाब

जबलपुर। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत सुर्खियों में हैं। अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर उन्हें तगड़ा झटका लगा है। पहले ही इस मूवी को लेकर विवाद चल रहा था और फिर सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) ने इसका सर्टिफिकेट रोक दिया। ऐसे में 6 सितंबर 2026 को रिलीज होने वाली इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया। एक तरफ कंगना बहुत निराश हैं तो दूसरी तरफ मप्र हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर सीबीएफसी से जवाब मांगा है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को फिल्म इमरजेंसी को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जज विनय सराफ की डिवीजन बेंच ऑफ एक्टिंग ने



अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि फिल्म को अभी तक प्रमाणित (सर्टिफिकेट) किया गया है या नहीं। हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने केंद्र सरकार की हाल की दलील पर भी गौर किया कि फिल्म को अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया है। जस्टिस सचदेवा ने कहा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर बोर्ड इस पर विचार कर रहा है। ऐसी संभावना है कि अगर कोई सन ऐसा है, जिसे एडिट करने या हटाने की जरूरत है... तो मुमकिन है कि फिल्म 6 तारीख को रिलीज

नहीं होगी। यह जनहित याचिका जबलपुर सिख संगत और गुरु सिंह सभा इंदौर द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील नरेंद्र पाल सिंह रूपरा ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता जबलपुर और इंदौर के कई गुरुद्वारों, स्कूलों और कॉलेजों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वकील नरेंद्र पाल सिंह रूपरा ने कहा कि इस मामले में सिनेमैटोग्राफ एक्ट का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर में अमृतधारी सिखों को लोगों की हत्या करते हुए दिखाया गया है और एक डायलॉग है कि 'आपको वोट चाहिए, हमें खालिस्तान चाहिए।' वकील ने कहा कि हमारे यहां छोटे बच्चे पटका पहनकर स्कूल जाते हैं और... वे छोटे बच्चे हैं और दूसरे लोग उन्हें खालिस्तानी कहकर चिढ़ाते हैं। भारतीय सेना में शामिल होना हर सिख का गौरव है।

अवश्यकता है

इंदौर भोपाल जिले के सभी तहसीलो में दैनिक अख़बार और डिजिटल रिपोर्टर की।

डिजिटल और प्रिंट के लिये मार्केटिंग टीम (मेल/फ़ीमेल) एवं हेल्परो की अवश्यकता हैं

डिजिटल मीडिया का क्रान्तिकारी कदम

डिजिटल भारत में खबरों के लिए देखे सिटी चीफ न्यूज़

रिपोर्टर बनने के लिए सम्पर्क करे



9755996590

रेलवे का भी हब बन जाएगा स्वच्छ शहर- 18 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

इंदौर-मुंबई के बीच बिछेगी नई रेल लाइन

दोनों शहरों की दूरी 100 किमी कम होगी

इंदौर। इंदौर से मुंबई की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दोनों शहरों के बीच 309 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाने का फैसला लिया गया है। यह रेल लाइन इंदौर से मुंबई के ही एक इलाके मनमाड के बीच बिछेगी। 18,036 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट 1000 गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत करेगा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने सोमवार को यह फैसला लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे मुंबई और इंदौर जैसे दो बड़े हब जुड़ सकेंगे। इस प्रोजेक्ट को 2028-29 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना से 102 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित होगा। इस परियोजना के तहत कुल 30 नए स्टेशन तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा आकांक्षी जिले बड़वानी की कनेक्टिविटी भी इससे मजबूत होगी। राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी के मुताबिक अभी इंदौर से मुंबई के बीच रेल मार्ग की दूरी 650 किलोमीटर है, लेकिन इंदौर मनमाड़ रेल लाइन के बाद दूरी 100 किलोमीटर घट जाएगी। इससे यात्रियों को समय और पैसे दोनों की बचत होगी। रेलवे को भी फायदा होगा।

‘पीएम-गतिशक्ति’ के तहत मंजूरी- रेल मंत्री ने बताया कि पीएम-गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे माल ढुलाई और यात्रियों को बड़ा फायदा होगा। इंदौर और मुंबई के बीच 309 किलोमीटर के इस नेटवर्क के तहत कुल 6 जिले पड़ेंगे। उन्होंने कहा इससे इन जिलों की कनेक्टिविटी और विकास को गति मिलेगी। यही नहीं मध्य भारत से पश्चिम और पश्चिम पश्चिम भारत की कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दोनों ही इलाकों



में पर्यटन की गतिविधियां भी तेज होंगी।

उज्जैन-इंदौर क्षेत्र का विकास तेज होने की संभावना- उम्मीद की जा रही है कि इससे उज्जैन-इंदौर क्षेत्र का विकास तेज होगा और महाकाल मंदिर पहुंचना भी पश्चिम भारत के लोगों के लिए आसान होगा। इसके अलावा मिलेट उत्पादन करने वाले मध्यप्रदेश के जिलों और प्याज उत्पादन करने वाले महाराष्ट्र के जिलों को कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे फसलों को पहुंचाने में भी आसानी होगी।

उत्पादों की ढुलाई आसान होगी- कहा जा रहा है कि इससे ऐग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, कंटेनर्स, स्टील, सीमेंट, पेट्रोलियम, तेल और ल्यूब्रिकेंट्स जैसे उत्पादों की ढुलाई पहले के मुकाबले काफी आसान हो सकेगी। इस परियोजना के तहत पूरे रूट पर 30 नए स्टेशन तैयार किए जाएंगे। इनसे 1000

गांवों तक पहुंचना आसान होगा और कुल 30 लाख लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा।

इस तरह 5.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर योजना-सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यह कृषि उत्पादों, उर्वरक, कंटेनर, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट (पीओएल) जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए यह एक आवश्यक मार्ग है। क्षमता वृद्धि के चलते प्रतिवर्ष करीब 2.6 करोड़ टन की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। बयान में यह भी कहा गया है कि रेलवे पर्यावरण अनुकूल तथा ऊर्जा कुशल परिवहन का साधन है। इससे जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की लॉजिस्टिक्स की लागत में कटौती करने, तेल आयात को घटाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी, जो 5.5 करोड़ पेड़ लगाने

के बराबर है।

पीथमपुर ऑटो क्लस्टर को होगा फायदा- परियोजना से पीथमपुर ऑटो क्लस्टर (90 बड़ी इकाइयां और 700 छोटे और मध्यम उद्योग) को जेएनपीए के गेटवे पोर्ट और अन्य राज्य बंदरगाहों से सीधा सम्पर्क मिलेगा।

इंदौर के लिए पहली बार होगा ऐसा- इंदौर से मुंबई की सीधी कनेक्टिविटी इस नई लाइन से पहली बार हो सकेगी। अभी तक इंदौर से मुंबई के लिए सीधा कोई रूट नहीं है। अभी मुंबई जाने के लिए खंडवा या फिर भोपाल होते हुए जाना पड़ता है। इंदौर से सनावद, ओंकारेश्वर पुरानी लाइन थी जो नवीनीकरण के कारण बंद पड़ी है। अभी यहां केवल पातालपानी टूरिस्ट ट्रेन चल पा रही है। बाकी पूरा रूट बंद है।

बड़वानी को मिलेगी पहली रेल लाइन- इस लाइन का सीधा फायदा

इंदौर संभाग के तीन बड़े आदिवासी बहुल जिलों को होगा। बड़वानी ऐसा जिला है, जहां से कोई ट्रेन नहीं गुजरती, न कहीं लाइन है। धार जिले में दाहोद-इंदौर लाइन का काम चल रहा है। इसके अलावा छोटा उदयपुर लाइन भी प्रस्तावित हुई थी। अब मनमाड की नई लाइन धार जिले से होकर जाने पर धार जिले में यह तीसरा रेल प्रोजेक्ट होगा। अभी इन दोनों जिलों में केवल बस या निजी वाहन ही एक से दूसरे शहर जाने के लिए साधन मौजूद हैं।

महाराष्ट्र वाले हिस्से का काम शुरू, अब मप्र की बारी- इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी कई बार सदन में रेल लाइन की मांग करते आए हैं। इस परियोजना से इंदौर से मुंबई के बीच की दूरी कम हो जाएगी। अभी इंदौर से गुजरात होकर ट्रेन मुंबई जाती है। इस परियोजना से निमाड़ क्षेत्र को भी लाभ होगा। राज्यसभा सांसद सुमेरसिंह सोलंकी ने बताया इस परियोजना के महाराष्ट्र वाले हिस्से का काम शुरू हो चुका है, लेकिन अब मध्यप्रदेश के हिस्से में भी काम होगा। पिछले साल इस परियोजना के लिए रेल मंत्रालय ने सर्वे भी कराया था। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सालभर पहले ही तैयार हो गई थी। मनमाड से धुले के बीच 60 किलोमीटर लंबाई में काम शुरू हो चुका है। इस ट्रेक पर 300 से ज्यादा छोटे-बड़े ब्रिज, 25 से ज्यादा स्टेशन बनेंगे। इसके अलावा घाट सेक्शन में सुरंगें भी बनेंगी। अब इंदौर रेलवे का भी हब बन जाएगा। इंदौर से दक्षिण के राज्यों के अलावा महाराष्ट्र के राज्यों की कनेक्टिविटी हो जाएगी।

तेजी से होगा इंदौर का विकास इंदौर-मनमाड रेल लाइन से इंदौर का विकास तेजी के साथ होगा। ट्रेन से

वंचित मप्र के जिलों में रेल लाइन पहुंच जाएगी। इंदौर का मुंबई और दक्षिण के राज्यों के बीच संपर्क आसान हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट 2028 तक पूरा होने की संभावना है।

-शंकर लालवानी, सांसद इंदौर

पहली बार इन शहरों से गुजरेगी रेल लाइन

-नई रेल लाइन महु से धार जिले के धरमपुरी, ठीकरी, राजपुर, सेंधवा, सिरपुर, शिखडी, धुले, मालेगांव से होकर मनमाड पहुंचेगी।

-पूरी परियोजना में 30 नए रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे।

-इंदौर-मुंबई के बीच सबसे छोटा रेल मार्ग बनेगा।

-मप्र के चार जिलों से होकर गुजरेगी रेल लाइन।

-महाराष्ट्र के दो जिले शामिल। पांच वर्ष में पूरी होगी परियोजना।

-पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के हजार से अधिक छोटे-बड़े उद्योगों को होगा सीधा फायदा। लाजिस्टिक सेक्टर को फायदा।

नई लाइन से होंगे ये फायदे

-महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन आने वाले महाराष्ट्र, दक्षिण और निमाड़ के लोगों के लिए सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी।

-धार, खरगोन, बड़वानी, नासिक, धुले की 30 लाख आबादी पहली बार ट्रेन से सीधी जुड़ जाएगी।

-पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया के सीधे मुंबई से जुड़ने से यहां की बड़ी कंपनियों को बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़ेगा।

-नासिक के प्याज और अंगूर जैसे उत्पाद सीधे इंदौर आ सकेंगे। निमाड़ की मक्का और ज्वार का ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा।

एयरपोर्ट पर पुराने टर्मिनल को शुरू कर बढ़ाई जाएगी उड़ानों की संख्या

बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा

इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्या बाई होल्कर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर प्रयास शुरू हो गए हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बनाने और रनवे का विस्तार करने का प्लान तैयार कर मुख्यालय भेजा गया है। नया टर्मिनल वर्तमान टर्मिनल के नजदीक बनाया जाएगा। मुंबई की तर्ज पर रनवे का विस्तार किया जाएगा, ताकि विदेशी कंपनियों के बड़े बोइंग विमान भी उतर सकें। वर्तमान टर्मिनल 1322 यात्री प्रतिघंटा की क्षमता से कार्य कर सकता है। कुछ चुनिंदा समय में एयरपोर्ट पर यात्रियों का अधिक दबाव रहता है। ऐसे में पुराने टर्मिनल से एटियार (छोटे विमान) और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जाएगा। इससे छह सौ यात्री प्रतिघंटा की क्षमता बढ़ जाएगी। इ। इस एक घंटे में एयरबस के तीन और एटियार के पांच आपरेशन अतिरिक्त संचालित



हो सकेंगे। इससे एयरपोर्ट पर उड़ानों की संख्या में भी बहुतेरी होगी। यह बात एयरपोर्ट के नए डायरेक्टर विपिनकांत सेठ ने सोमवार को कही। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का विकास और यात्री सुविधाओं पर उनका फोकस रहेगा। यह बात एयरपोर्ट के नए डायरेक्टर विपिनकांत सेठ ने सोमवार को कही। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का विकास और

यात्री सुविधाओं पर उनका फोकस रहेगा। एक करोड़ सालाना क्षमता का नया टर्मिनल बनने तक पुराने टर्मिनल का उपयोग उड़ानों के संचालन के लिए किया जाएगा। इसके लिए नवनिर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। नौ माह में सभी कार्य पूरे कर पुराने टर्मिनल को शुरू कर दिया जाएगा। यहां पर यात्रियों के लिए सभी तरह की सुविधाएं जुटाई जाएंगी। फायर और

अन्य अनुमतियों के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद एयरपोर्ट की 40 प्रतिशत यात्री क्षमता बढ़ जाएगी।

उड्डयन मंत्री वर्चुअली करेंगे डीजी यात्रा की शुरुआत- इंदौर एयरपोर्ट पर छह सितंबर को डीजी यात्रा (चेहरा पहचान प्रणाली) का शुभारंभ नागरिक उड्डयन मंत्री किजरापु राममोहन नायडू विशाखापट्टनम से करेंगे। इंदौर में डीजी यात्रा का शुभारंभ वर्चुअली होगा। इसके साथ आठ अन्य एयरपोर्ट पर भी डीजी यात्रा की शुरुआत होगी। इस सुविधा का उपयोग करने वाले यात्रियों को कागजात दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। इंदौर एयरपोर्ट पर विगत कुछ समय से रिटेल काउंटर बंद हो चुके हैं। इन काउंटर्स को फिर से शुरू किया जा रहा है। अक्टूबर में छह रिटेल काउंटर का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी यात्रियों के लिए जुटाई जाएंगी।

इंदौर। 7 साल की बालिका के साथ ज्यादाती के मामले में आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पीड़िता घर में अकेली थी। माता-पिता काम पर गए थे। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के मुताबिक न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुश्री सविता जड़िया इंदौर ने थाना लसूडिया के केस में फैसला सुनाया है। आरोपी राघवेंद्र उर्फ रामू उम्र 20 साल निवासी ललितपुर जिला झांसी को पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय मीणा द्वारा की गई।

16 जून 2023 को पीड़िता की मां लसूडिया थाने गई थी। पुलिस को बताया था कि वह चॉकलेट फैक्ट्री में काम करती है। उसके पति मिस्त्री का काम करते हैं। 15 जून 2023 को सुबह वह और



उसके पति काम पर गए थे। 7 साल की बेटी और 4 साल का बेटा घर पर थे। रात को 8.30 काम कर वापस घर लौटी तो उसके मकान मालिक ने बताया कि दिन में आरोपी घर आया था। बच्ची पीड़िता और आरोपी कमरे के अंदर थे। दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा बजाने पर भी नहीं खोल रहे थे।

तब उसने बच्ची से पूछा तो उसने बताया कि वह दिन में कपडे

धो रही थी। उसका भाई घर के बाहर रेली में खेल रहा था तभी आरोपी आया और अंदर से दरवाजे बंद कर दिया और उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। अजिमा से आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।

दो युवक दे रहे थे धमकी, 18 साल की लड़की ने कर ली आत्महत्या

युवक की हत्या के बाद लाश ठिकाने लगाने वाला आरोपी भी गिरफ्तार

इंदौर। इंदौर में 18 वर्षीय युवती कोमल पांडे ने सुसाइड कर लिया। वह रीवा के दो युवकों द्वारा धमकी दिए जाने से परेशान थी। पुलिस और सीएम हेल्पलाइन से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे वह और अधिक परेशान हो गई। दोनों युवक उसे धमकाते थे कि हमारी बात नहीं मानेगी तो तुझे मार देंगे। तेरी कहीं पर भी शादी नहीं होने देंगे। साहिल और गोलू से परेशान कोमल ने आखिर हार मान ली। किसी ने उसकी मदद नहीं की न ही पिता की शिकायतों पर किसी ने सुनवाई की। कोमल के पिता हनुमान पांडे ने बताया कि उनकी बेटी को रीवा के ग्राम कोनिया तहसील त्योंथर में रहने वाला



साहिल और गोलू नाम का युवक अलग-अलग नंबरों से कॉल कर धमका रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों युवक उनकी बेटी पर बात करने के लिए दबाव बना रहे थे और धमकी दे रहे थे कि अगर वह उनकी बात नहीं मानेगी तो

वह उसकी जान से खत्म कर देंगे और उसकी शादी नहीं होने देंगे। कोमल के पिता ने कहा कि उन्होंने इस मामले में शिकायत करने एमआईजी थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कहा कि मामला रीवा का है इसलिए वहीं

जाकर शिकायत करो। इसके बाद उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, लेकिन दोनों आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोमल के पिता ने बताया कि उनकी बेटी घर पर ही रहती थी और तीन साल पहले उनकी मां की मौत हो गई थी। बड़ी बहन की शादी नागपुर में हो चुकी है और भाई जन्माष्टमी से नागपुर में बहन के पास गया है। सूचना के बाद परिवार के लोग इंदौर आ रहे हैं। इस मामले में पुलिस की लापरवाही और सिस्टम की विफलता सामने आई है। पुलिस को इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को सजा दिलानी चाहिए।

इंदौर। सिलोकान सिटी निवासी गजानंद परिहार की हत्या का चौथा आरोपी अजीत चौहान भी पकड़ा गया है। अजीत ने ही गजानंद की लाश ठिकाने लगाई थी। इसके बदले मुख्य आरोपी आशीष पंवार से पांच हजार रुपए मांगने के कारण परेशान था। उसने मुहबोले साले धीरज और राहुल के साथ गजानंद को मारने का षड्यंत्र रचा। 24 अगस्त को आशीष को रूपए के लिए बुलाया और कार से पातालपानी की तरफ ले गया। साजिश के मुताबिक रस्सी से गला घोंटा और गजानंद की हत्या कर दी। आरोपी कार

की डिककी में शव रखकर घूमते रहे। फिर सिलोकान सिटी तक आए और रेलवे स्टेशन पर खड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस के बाथरूम में गजानंद का मोबाइल रखवा दिया। फिर शव को बंधाना के जंगलों में गाड़ दिया। बाहर निकलने का शक हुआ तो आरोपी कार लेकर फिर से शव को देखने भी गए। आशीष ने सिंधाना के अजीतसिंह चौहान की मदद ली और उससे कहा कि शव को ठिकाने लगाने में मदद करें। आशीष ने अजीत को पांच हजार रुपए भी दिए। चारों आरोपी बोरे में भरा शव कार में डालकर ले गए और राजपुर थाना अंतर्गत फेंक दिया। टीआई राजपालसिंह राठौर के मुताबिक पुलिस ने बड़वानी पुलिस से मर्ग डायरी लेकर गुरुवार को चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। अजीत को गिरफ्तार कर लिया है।

जल जमाव को लेकर कसावट, बारिश का पानी जमा होने पर जेडओ सस्पेंड

इंदौर। इंदौर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने सोमवार को कई जोन में निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान एक स्थान पर बारिश का पानी जमा दिखा और निकासी नहीं होने पर उन्होंने जमकर नाराजगी जताई। इसके लिए जिम्मेदार जोन-22 के जोनल अधिकारी दौलत सिंह गुडिया को सस्पेंड कर दिया। दरअसल इन दिनों बारिश के पानी के जलजमाव को लेकर ट्रैफिक जाम के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पिछले दिनों खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अधिकारियों से तलब कर चुके हैं। सोमवार दोपहर निगम कमिश्नर ने जोन-22 के निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर बारिश का पानी जमा होने, उसकी निकासी नहीं करने पर और सफाई व्यवस्था में काफी लापरवाही पाई। इस पर उन्होंने तत्काल प्रभाव से जोनल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने विजय नगर चौराहा, रेडिसन, बाँबे हॉस्पिटल चौराहा, निपानिया, महालक्ष्मी रोड, सत्य साईं चौराहा आदि का दौरा किया। साथ ही चेब्रों की नियमित सफाई का भी अवलोकन किया गया।

मरीजों को 4 घंटे करना पड़ रहा इंतजार, रोज 200 मरीजों का होता है एक्स-रे जिला अस्पताल में 2 माह से नहीं सुधार पा रही एक्सरे मशीन

भोपाल। राजधानी भोपाल के जिला अस्पताल जेपी में एक्स-रे मशीन खराब होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। अस्पताल में तीन मशीनों में से केवल एक मशीन चल रही है। मरीजों को चार-चार घंटे एक्स-रे के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि यहां दो मशीन करीब 2 महीने से बंद पड़ी है। प्रबंधन बार-बार यही तर्क देता है की मशीन को रिपेयर किया जा रहा है। रोजाना जेपी में हर दिन लगभग 200 एक्स-रे होते हैं लेकिन वर्तमान में आधे ही हो पा रहे हैं। दरअसल जेपी अस्पताल में एक्सरे की तीन मशीनों में से दो बंद पड़ी हैं। अस्पताल के ब्लॉक बी में संचालित दोनों मशीनें बंद हैं। वहीं सिर्फ ए ब्लॉक में लगी मशीन ही चल रही है। गौरतलब है कि जेपी समेत स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में डिजिटल एक्सरे सभी मरीजों के लिए फ्री कर दिया गया है। जिसके बाद से अस्पताल में एक्सरे कराने वालों की संख्या दो गुना से अधिक बढ़ गई है। निजी अस्पताल व क्लीनिक में इलाज कराने वाले मरीज भी जांच के लिए अस्पताल आ रहे हैं। ऐसे में डिजिटल मशीन पर उसकी क्षमता से ज्यादा लोड पड़ रहा है। यही कारण है कि ब्लॉक बी की



मशीन बार बार खराब हो रही है। वहीं एक अन्य मशीन को कंडम करने की प्रक्रिया चल रही है। जिससे उसके स्थान पर नई मशीन खरीदी जा सके।
अस्पताल में रेडियोग्राफरों की कमी- राजधानी के जिला अस्पताल जेपी में एक्स-रे करने वाले रेडियोग्राफरों की कमी है, नई भर्ती नहीं होने से परेशानी बढ़ती जा रही है। यहां आउट सोर्स कर्मचारियों से काम चलाया जा

रहा है। दरअसल एक्स-रे जांच के लिए एक समय पर तीन कर्मचारियों की जरूरत होती है। एक कर्मचारी रजिस्ट्रेशन के लिए, एक कंप्यूटर पर और एक कर्मचारी मशीन को हेंडल करने के लिए जरूरी है। ऐसे में तीन मशीनों के लिए 9 कर्मचारियों की जरूरत है। जबकि अस्पताल के पास एक्सरे की जांच के लिए वर्तमान में पांच ही कर्मचारी हैं।
जल्द शुरू हो जाएगी

मशीन- जेपी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. रीकेश श्रीवास्तव का कहना है कि मशीन का कुछ टेक्निकल परेशानी आ रही है। मशीन को सुधारने का काम चल रहा है। एक दो दिन में शुरू हो जाएगी। मरीजों की सुविधा के लिए दूसरी मशीन को देर समय तक चलाया जा रहा है। मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो यह प्रयास किया जा रहा है।

कॉल डिटेल और विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी के फुटेज से हुआ हत्या का पर्दाफाश पत्नी से फोन पर बात करने पर काट दिया था दोस्त का गला

भोपाल। बिलखिरिया थाना पुलिस ने 24-25 अगस्त की दरमियानी रात आरटीओ के पास हुई छावनी पठार निवासी 22 सुप्यार शिल्पी ऐर्फं छोटू की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। वह राजमिस्त्री का काम करता था। हत्या के आरोप में छोटू के दोस्त 33 वर्षीय रामबाबू कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। छोटू, रामबाबू की पत्नी से फोन पर बात किया करता था। इससे नाराज होकर उसने साथ में शराब पिलाने के बाद चाकू से छोटू का गला रेत दिया था। बिलाखिरिया थाना प्रभारी वीरेंद्र सेन के अनुसार 26 अगस्त को दोपहर में छोटू का शव झाड़ियों से बरामद किया गया था।



उसका मोबाइल फोन गायब था। मोबाइल की कॉल डिटेल और विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी के फुटेज देखने पर पता चला था कि आखिरी बार छोटू अपने दोस्त

रामबाबू के साथ देखा गया था। घटना के बाद से रामबाबू गायब भी था। पुलिस ने रविवार को मूलतः ग्राम उमरहारी थाना सुल्तानगंज थाना सिलवानी को

हिरासत में ले लिया। पूछताछ में रामबाबू ने पुलिस को बताया कि छोटू उसकी पत्नी से फोन पर लंबी बात किया करता था। उसने कई बार छोटू को समझाया भी था, लेकिन वह नहीं मान रहा था।
शराब पिलाने के बहाने ले गया- 24 अगस्त की को वह शराब पिलाने के बहाने से छोटू को अपने साथ ले गया था। नशा अधिक होने पर उसने छोटू के गले पर चाकू से वार कर दिए थे। इससे उसकी मौत हो गई थी। एएसआइ बेनीप्रसाद ने बताया कि रामबाबू ने छोटू का मोबाइल फोन रायसेन बायपास रोड पर फेंक दिया था। उसे भी बरामद कर लिया था।

कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी को हटाने की तैयारी, अध्यक्ष से नहीं बैठ रही पटरी दो प्रदेशों का प्रभार हो से एक की कमान ली जा सकती है वापस

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह को प्रदेश प्रभारी पद से हटाने की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि जितेंद्र भंवर सिंह और मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की तालमेल नहीं बैठ रहा है। यही वजह है कि अब भंवर जितेंद्र सिंह से मध्य प्रदेश की कमान वापस लेने की तैयारी की जा रही है। दरअसल भवर जितेंद्र सिंह के पास असम और मध्यप्रदेश दो राज्य का प्रभार है। ऐसे में अब उनसे एक राज्य की कमान वापस ली जा सकती है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मध्य प्रदेश को नया प्रदेश प्रभारी मिल सकता है। इधर कांग्रेस के इस उलट फेर की चर्चा के बीच भाजपा नेता चुटकी ले रहे हैं नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो रही है। सिंह लंबे समय से असम की कमान संभाल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार के बाद



भंवर जितेंद्र सिंह को मध्यप्रदेश की जिम्मेदारी मिली थी। मध्यप्रदेश की कार्यकारिणी को भंग हुए 8 महीने हो गए हैं लेकिन अबतक नई टीम नहीं बन पाई है। जिसको देखते हुए कहा जा रहा है कि जल्द ही भंवर जितेंद्र सिंह की मध्य प्रदेश से छुट्टी होने की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि अगले एक हफ्ते में कांग्रेस महासचिव की लिस्ट जारी होने

वाली है।
बीजेपी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों के षड्यंत्र का आरोप- कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा कि ये सब बीजेपी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों का षड्यंत्र है। कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है। कई मामलों पर ऐसी जोरों पर है। कहा जा रहा है कि मुलाकात और दौरे होती हैं। कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन कर

सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया समेत विभागों में जिम्मेदारी भी दी जा रही है। नई कार्यकारिणी के चलते काम प्रभावित नहीं है। विपक्षी पार्टियों की राजनीति का तरीका है। जनता हमारे साथ खड़ी और बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है।
दिल्ली का चक्कर काट रहे जीतू पटवारी- भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि जीतू पटवारी प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह को हटाने के लिए दिल्ली चक्कर काट रहे हैं, उधर, जितेंद्र दाल नहीं गलने दे रहे जीतू पटवारी की। कांग्रेस बना अखाड़ा और दिल्ली बना मैदान। कांग्रेस अब खत्म की ओर है। 05 लाख कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से हाथ जोड़े। 15 जिलों में जिलाध्यक्ष और प्रदेश में कार्यकारणी नहीं है। जितेंद्र सिंह और पटवारी की लड़ाई कांग्रेस कार्यालय में ताला लगावाएगी।

नियमितीकरण को लेकर अतिथि शिक्षक आंदोलन की राह पर

भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी करने वाले अतिथि शिक्षक नियमितीकरण को लेकर एक बार फिर आंदोलन की राह पर आ गए हैं। दरअसल अतिथि शिक्षक लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे। पिछले साल 3 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अतिथि शिक्षक पंचायत में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का ऐलान किया था। वादा पूरा नहीं होने पर सोमवार को अतिथि शिक्षकों ने रैलियां निकालीं। वहीं, 5 सितंबर को भोपाल में करीब 70 हजार अतिथि शिक्षक तिरंगा यात्रा निकालेंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 6 साल पहले अतिथि शिक्षकों के समर्थन में तत्कालीन मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र एक्स पर शेयर करते हुए गेस्ट टीचर्स को नियमित करने की मांग की है।

जब आप विधायक थे तो अतिथि शिक्षकों के पक्ष में को लिखते थे पत्र - दिग्विजय सिंह ने डॉ एक लेटर को शेयर करते हुए लिखा कि डॉ. मोहन यादव जब आप विधायक थे, तब आप अतिथि शिक्षकों के पक्ष में सीएम को पत्र लिखते थे। अब प्रभु कृपा से आप खुद सीएम है, तो अतिथि शिक्षकों का अनुभव व योग्यता के आधार पर नियमित करने की कृपा करें। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 15 मार्च 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र



लिखा था। उन्होंने पत्र में लिखा था कि अतिथि शिक्षक संगठन समिति जिला उन्जैन मप्र. द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत अतिथि शिक्षक 8 से 10 वर्षों से निरंतर पूर्ण निष्ठा से अध्यापन एवं अन्य अनुषांगिक कार्य कर रहे हैं। वर्ग-1 अतिथि शिक्षकों को 4500 रुपए वर्ग-2 अतिथि शिक्षकों को 3500 रुपए और वर्ग-3 को 2200 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जो कि दैनिक मजदूरी की तुलना में भी कम है। इनकी लम्बी सेवा अवधि एवं इन्हें संविदा शिक्षक बनाए जाने की कार्यवाही अपेक्षित है। संघ द्वारा मुझे इस संबंध में जो ज्ञापन दिया गया है, वह पत्र के साथ प्रेषित कर रहा हूं। कृपया ज्ञापित तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर अतिथि शिक्षकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए मांगों के निराकरण हेतु यथावश्यक

निर्देश प्रसारित करने का अनुरोध करता हूं।
प्रदेश के सभी जिलों में रैली निकालकर सरकार को वचन दिलाया याद- अतिथि शिक्षक महासंघ के बैनर तले प्रदेश के समस्त जिलों में रैली निकालकर सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा याद दिलाया । संगठन के पदाधिकारियों का कहना है मुख्यमंत्री बदले हैं सर नहीं बदली, हर हाल में घोषणा के आदेश जारी करें । महासंघ के पदाधिकारी लगातार पूरे प्रदेश में बैठकों का आयोजन कर संख्याबल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पदाधिकारियों ने सरकार चेतवानी दी है कि यदि शीघ्र आदेश जारी नहीं हुए तो 5 सितंबर को रोशन पुरा चौराहे भोपाल से रैली निकालकर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। जिसमें प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षक शामिल होंगे ।

कांग्रेस नेता ने अधिकारी पर गुमटी हटाने और जेल भिजवाने का लगाया आरोप

दिव्यांग को गोद में लेकर पहुंचे और टेबल पर कर दिया खड़ा

भोपाल। राजधानी भोपाल मे कांग्रेस नेता ने एक दिव्यांग की परेशानी का निवारण अलग तरीके से किया। दरअसल कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला सोमवार को एक दिव्यांग व्यक्ति उमाशंकर नन्हेंटे को गोद में उठाकर निगम ऑफिस पहुंचे और कमिश्नर हरेंद्र नारायण यादव के सामने टेबल पर खड़ा कर दिया। शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांग की जबर्दस्ती गुमटी हटाई गई। उसे जेल भेज दिया गया। ये कहां का न्याय है? इस मामले में निगम कमिश्नर ने जांच कराने के आदेश दिए हैं। शुक्ला ने बताया कि उमाशंकर नन्हेंटे वार्ड 58 के गौतम नगर इलाके में पिछले 15 सालों से फास्टफूड की गुमटी लगाते हैं और अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। दिव्यांग व्यक्ति उमाशंकर नन्हेंटके को गुमटी नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी शैलेन्द्र सिंह भदौरिया ने द्वेषपूर्ण भावना से न सिर्फ हटाय़ा बल्कि गुमटी सहित आजीविका का पूरा सामान जब्त कर लिया। उनका इतने से भी मन नहीं भरा हो पीड़ित पर मामला दर्ज कराकर दोषी को गोविंदपुरा थाने में उसे बंद करा दिया। थाने से जमानत भी नहीं होने दी, मजबूरन गरीब परिजनों ने अदालत से उनकी जमानत



कराई। शुक्ला ने इस पूरे मामले की जानकारी नगर निगम कमिश्नर को देते हुए बताया कि अतिक्रमण अधिकारी ने स्थानीय विधायक के दवाब में एक गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ यह अन्याय किया। सरकार दिव्यांगजनों और अनुसूचित जाति की हमदर्द बनती है लेकिन राजधानी में सरकार की नाक के नीचे ही ऐसा अन्याय हो रहा है। अदालत ने भी पीड़ित को जमानत देते हुए स्वयं कहा कि पीड़ित की जमानत थाने से हो सकती है, कोर्ट आने की जरूरत नहीं थी। शुक्ला ने बताया कि 15 सालों से इसी स्थान पर गुमटी लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाले उमाशंकर नन्हेंटे विकलांग हैं, और गुमाश्ता

लायसेंस उनकी पत्नी के नाम है। अतिक्रमण अधिकारी ने उनके उपर अनर्गल आरोप लगाते हुए उनके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया है। उन्होंने कमिश्नर से मांग की कि अतिक्रमण अधिकारी पर कार्यवाही की जाए और पीड़ित उमाशंकर नन्हेंटे को न्याय देते हुए उनका सामान वापस कराकर उन्हें दोबारा से अपनी दुकान संचालित करने में नगर निगम सहयोग करे। इस दौरान सैयद तारिक अली, अमित खत्री, मुकेश पंथी, प्रिस नवांगे, महेश मेहरा, उल्लास सोनकर, राजकुमार राय, सुरेश साहू, अनूप पांडे, जितेंद्र सिंह बघेल, योगेश प्रजापति, सुशील ठाकुर, संजय डूमने, हर्षित तिवारी, फैजान खान, मो आमिर, अलमास अली आदि मौजूद थे।

सोमवती अमावस्या पर मंदिर जा रहे थे ग्रामीण, 18 घायल गाय को बचाने में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 4 की मौत

भोपाल। मध्य प्रदेश के दमोह में सोमवार को श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, दमोह जिले के मगरौन थाना अंतर्गत फतेहपुर चौकी क्षेत्र के तालाब के पास रविवार देर रात श्रद्धालुओं से भरी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मगरौन थाना और फतेहपुर चौकी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की की मदद से घायलों और मृतकों को हटा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। वहीं गंभीर हालत वाले 8 लोगों को प्राथमिक इलाज के बाद दमोह जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान दो लोगों की और मौत हो गई।



रास्ता साफ नहीं दिख रहा था, फिर भी तेज रफ्तार

बताया जा रहा है सभी श्रद्धालु सोमवती अमावस्या पर दमोह जिले के बटियागढ़ ब्लॉक के घुघस गांव से छतरपुर जिले के जटाशंकर धाम जा रहे थे। घायलों की मानें तो सड़क पर अचानक गाय सामने आ जाने से गाय को बचाने के चलते ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और हादसा हो गया। घायलों ने बताया कि रात का समय था, रास्ता साफ नहीं दिख रहा था और ट्रैक्टर तेज रफ्तार में चल रहा था तभी अचानक सामने से गाय आ गई, गाय को बचाने की कोशिश में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने यह हादसा हो गया।

संपादकीय

राष्ट्रपति ने आम आदमी की पीड़ा को दी अभिव्यक्ति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पेंडिंग केस और बैकलॉग न्यायपालिका के लिए बड़ा चैलेंज हैं। जब रेप जैसे मामलों में कोर्ट का फैसला एक पीढ़ी गुजर जाने के बाद आता है, तो आम आदमी को लगता है कि न्याय की प्रक्रिया में कोई संवेदनशीलता नहीं बची है। जब रेप जैसे मामलों में तत्काल न्याय नहीं मिलता तो लोगों का भरोसा उठ जाता है।

राष्ट्रपति ने आम आदमी की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में सर्वोच्च न्यायालय के आह्वान पर राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन हुआ। रविवार को इसी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचीं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पेंडिंग केस और बैकलॉग न्यायपालिका के लिए बड़ा चैलेंज हैं। जब रेप जैसे मामलों में कोर्ट का फैसला एक पीढ़ी गुजर जाने के बाद आता है, तो आम आदमी को लगता है कि न्याय की प्रक्रिया में कोई संवेदनशीलता नहीं बची है। जब रेप जैसे मामलों में तत्काल न्याय नहीं मिलता तो लोगों का भरोसा उठ जाता है। राष्ट्रपति ने आम आदमी की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। उनके इस भाषण को अजमेर के चर्चित छात्राओं के ब्लैकमेल कर रेप करने की घटना से जोड़ दें तो स्थिति उससे भी भयावह दिखती है, जिस ओर राष्ट्रपति का इशारा है। अजमेर में करीब 34 वर्ष पूर्व सौ से अधिक स्कूली छात्राओं से दुष्कर्म कर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। कहते हैं इसमें अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी से जुड़े कई लोगों के नाम भी आए थे। इसलिए पुलिस ने पहले रुचि नहीं ली। आंदोलन के बाद केस दर्ज हुए। 32 वर्ष बाद, अभी एक माह पूर्व उसका फैसला वहां की अदालत ने सुनाया। यह स्वाभाविक सवाल सबके मन में उठेगा की 32 वर्षों तक आखिर अदालत क्या करती रही? 32 साल बाद आए फैसले को क्या न्याय कह सकते हैं? यह तो न्याय का उपहास है। उन पीड़ित बच्चियों का उपहास है। रेप समेत सभी केसों में यही स्थिति है। चर्चित निर्भय केस में अपराधी को 12 वर्ष बाद फांसी दी जा सकी। देश की विभिन्न अदालतों में अभी 5 करोड़ से अधिक मुकदमों पेंडिंग हैं। देश में रेप की बढ़ती घटनाओं के पीछे देरी से सजा मिलना भी एक बड़ी वजह है। दुष्कर्म जानता है की वह मुकदमें को जितने साल चाहे लंबा खिंच सकता है। इस बीच पीड़ित को डरा धमकाकर केस को कमजोर कर दिया जाता है और अंततः दुष्कर्म बरी हो जाता है। सिस्टम की सुस्ती से अपराधियों का हौसला बढ़ता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही कानून का डर भी खत्म हो जाता है। एनसीआरबी के मुताबिक देश में प्रति 16 मिनट पर एक रेप और हर घंटे महिलाओं के विरुद्ध 50 अपराधिक घटनाएं हो रही हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कहा है कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम तारीख पर तारीख की पुरानी संस्कृति को बदलने का संकल्प लें। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के मुताबिक केस लंबे समय तक पेंडिंग क्यों पड़े रहते हैं, इसका कड़ाई से एनालिसिस करने किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर एक जैसे मामलों की एक साथ सुनवाई की जाएगी तो इससे कोर्ट में पेंडिंग मामलों को कम करने में मदद मिलेगी। मेघवाल ने कुछ हाईकोर्ट की तारीफ की, जो ऐसे सिस्टम पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने 'सभी के लिए न्याय' का टारगेट रखा है। राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन में प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लॉबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए एक ठोस योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तीन मुख्य चरण हैं। जिसमें पहले चरण में जिला स्तर पर मामलों के प्रबंधन के लिए समितियों का गठन किया जाएगा। ये समितियां लॉबित मामलों और रिकॉर्ड की स्थिति की जांच करेंगी। दूसरे चरण में, उन मामलों का निपटारा किया जाएगा जो 10 से 30 वर्षों से अधिक समय से लॉबित हैं। तीसरे चरण में, जनवरी 2025 से जून 2025 तक दस वर्षों से अधिक समय से लॉबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके लिए विभिन्न तकनीकी और डेटा प्रबंधन प्रणालियों की जरूरत होगी। लॉबित मामलों से निपटने के अन्य उपायों में विवादों का समाधान करने की पहल भी शामिल है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की, जिसमें 1,000 से ज्यादा मामलों का समाधान किया गया। प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि हमें यह स्थिति बदलनी होगी कि हमारे जिला न्यायालयों में केवल 6.7 फीसदी इन्फ्रास्ट्रक्चर ही महिलाओं के अनुकूल है। आज के समय में जब कुछ राज्यों में भर्ती में 60 फीसदी से 70 फीसदी महिलाएं हैं, तो क्या यह स्वीकार्य है? हमारी प्रार्थनाएं हैं कि न्यायालयों तक पहुंच को बढ़ाया जाए। इसके लिए हम इन्फ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट करेंगे, कोर्ट में मेडिकल सुविधाएं आदि स्थापित करेंगे और ई-सेवा केंद्र व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों का उपयोग बढ़ाएंगे। इन प्रयासों का मकसद न्याय तक सभी की पहुंच को आसान बनाना है। उन्होंने कहा, इसके साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे न्यायालय समाज के सभी लोगों के लिए सुरक्षित और अनुकूल हों, खासतौर पर महिलाओं, दिव्यांगों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य संवेदनशील समूहों के लिए।

भारत में सांपों से जूझती ग्रामीण आबादी

केंद्रीय स्वास्थ्य जांच ब्यूरो की रिपोर्ट (2016-2020) के अनुसार, भारत में सर्पदंश के मामलों की औसत वार्षिक आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) लगभग 3 लाख है और लगभग 2000 मौतें सर्पदंश के कारण होती हैं। जबकि सच्चाई यह है कि भारत में सर्पदंश से होने वाली मौतों की वास्तविक संख्या किसी के पास नहीं है।

सांप को देखते ही शरीर में सिहरन दौड़ पड़ती है। मनुष्य की इस स्वाभाविक प्रतिक्रिया से समझा जा सकता है कि आखिर झाड़ियों, घास में और बिल में दुबका हुआ सांप कितना खतरनाक होता है। बरसात के इन दिनों में धान आदि की खेती का मौसम है और यही समय सर्पदंश के लिए सर्वाधिक जोखिमपूर्ण है। दरअसल, सांप के काटने की घटनाएं ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में घटती हैं। इससे आम किसान या कृषि श्रमिक और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बच्चों को अकसर वयस्कों की तुलना में अधिक गंभीर प्रभाव झेलना पड़ता है, क्योंकि उनका शरीर का वजन कम होता है। जहरीले सांपों के काटने से कुछ ही समय में मौत से लेकर लकवा, सांस लेने में दिक्कत, रक्तस्राव संबंधी विकार से घातक रक्तस्राव, अपरिवर्तनीय किडनी फेल्योर, उतक क्षति से स्थायी विकलांगता और अंग विच्छेदन हो सकता है। यह समस्या मुख्य रूप से विकासशील देशों की और खास कर कृषि प्रधान ग्रामीण और वनवासी जनजातियों की है। यह समस्या न केवल स्वास्थ्य संकट पैदा करती है बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी डालती है। लेकिन इस समस्या को किसी भी स्तर पर मानव वन्यजीव संघर्ष की अन्य घटनाओं की तरह गंभीरता से नहीं लिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार दुनियाभर में हर साल 50.40 लाख लोग सांपों द्वारा काटे जाते हैं और 81,410 से लेकर 1,37,880 तक लोग सर्पदंश से मर जाते हैं तथा लाखों लोग विकलांगता और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। भारत का यह आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है। हालांकि सर्पदंश पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन और नेशनल क्राइम रिकार्डब्यूरो के आंकड़ों में भारी अंतर है। फिर भी सरकार द्वारा गत 12 मार्च 2024 को भारत में सर्पदंश से होने वाली मौतों की रोकथाम और



नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत के समय जारी विवरण के अनुसार भारत में हर साल लगभग 3-4 मिलियन सर्पदंशों में से लगभग 50,000 मौतें होती हैं, जो वैश्विक स्तर पर होने वाली सभी सर्पदंश मौतों का आधा हिस्सा है। इधर, विभिन्न देशों में सर्पदंश के शिकार लोगों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही क्लीनिकों और अस्पतालों में रिपोर्ट करता है और सर्पदंश के वास्तविक बोझ की रिपोर्ट बहुत कम की जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य जांच ब्यूरो की रिपोर्ट (2016-2020) के अनुसार, भारत में सर्पदंश के मामलों की औसत वार्षिक आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) लगभग 3 लाख है और लगभग 2000 मौतें सर्पदंश के कारण होती हैं। जबकि सच्चाई यह है कि भारत में सर्पदंश से होने वाली मौतों की वास्तविक संख्या किसी के पास नहीं है, क्योंकि ले घटनाएं अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों और वन बस्तियों में होती हैं और लोग सांप के काटने पर झाड़ फूंक और घरेलू इलाज पर समय बरबाद कर देते हैं। समय पर सही उपचार न मिलने पर सर्प दंशित व्यक्ति जान गंवा बैठता है। पुलिस और अस्पताल तक मामले न जाने के कारण उनकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती। भारत में मानसून का मौसम, जो आमतौर पर जून से सितंबर तक चलता है, सांप के काटने के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील अवधि होती है। मानसून में भारी बारिश होती है। भारी बारिश से सांपों के आवास नष्ट होते हैं और उनके बिलों में पानी भरता है। इससे सांप भोजन और आश्रय की तलाश में मनुष्यों के रहने वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं। मानसून का मौसम कृषि गतिविधियों के लिए भी सबसे अच्छा समय होता है। खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूर अनजाने में उन सांपों के संपर्क में आ सकते हैं जो ऊंची घास या मलबे के नीचे शरण लिए हुए होते हैं। माना जाता है कि मानसून के दौरान नमी का उच्च स्तर सांपों को अधिक सक्रिय बना सकता

है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्म, गीली परिस्थितियों में शिकार की उपलब्धता बढ़ सकती है, जिससे सांपों की अधिक गतिविधि हो जाती है। भारत की जनसंख्या बढ़ते जाने के साथ ही अन्य मानव-जीव संघर्ष की तरह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मानव-सांप संघर्ष भी बढ़ता जा रहा है। मानव निवास विस्तार प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण करता है। लोगों और सांपों के बीच यह बढ़ा हुआ सम्पर्क विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, सांप के काटने की संभावना को बढ़ाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से भी सांपों के व्यवहार और वितरण को प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए, गर्म तापमान और बदले हुए वर्षा पैटर्न उन आवासों का विस्तार कर सकते हैं जहां सांप रहते हैं और उनकी गतिविधि बढ़ सकती है। वनों की कटाई और कृषि विस्तार के कारण वन क्षेत्रों का नुकसान सांपों को भोजन और आश्रय की तलाश में मानव बस्तियों में पलायन करने के लिए मजबूर कर रहा है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर चिकित्सा सहायता और एंटीवेनम तक पहुंच सीमित होने के कारण उपचार में इस देरी से मृत्यु दर में वृद्धि होती है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने सर्पदंश से होने वाली मौतों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है जिसका विजन और मिशन सांप के काटने से होने वाली मौतों और विकलांगता के मामलों की संख्या को 2030 तक आधा करने के लिए इसे रोकना और नियंत्रित करना है। लेकिन इस जानलेवा समस्या का असली निदान सावधानी और प्रकृति के साथ जीने की कला सीखना ही है। यही नहीं हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि सांप मूलतः हमारा शत्रु नहीं है। वह बिना छेड़े हमला नहीं करता। कुछ मायनों में वह किसान का शत्रु नहीं मित्र ही है। अगर सांप न हो तो चूहे फसल बरबाद कर देंगे। वाइल्ड लाइफ एसओएस के

अनुसार भारत में सांपों की 11 परिवारों की लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें जिनमें से 60 से अधिक विषैले, 40 हल्के रूप से विषैले और लगभग 180 जहर रहित प्रजातियां हैं। इनमें कोबरा, रसेल और वापर जैसे प्रजातियां बेहद खतरनाक जहरधारी होती हैं। जबकि जहर रहित सैकड़ों प्रजाति के सांप अकारण ही मारे जाते हैं। सांप अन्य खूंखार जीवों की तरह हमला नहीं करता है इसलिए सावधानी में ही बचने का सुरक्षित उपाय है। सांप आमतौर पर छिपे हुए होते हैं, इसलिए जहां भी आप जाते हैं, खासकर घास, झाड़ियों, और ढीली चट्टानों के आसपास वहां सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे क्षेत्रों में जाते समय लंबी पैंट और मजबूत जूते पहनने चाहिए इससे आपकी त्वचा को सांपों के काटने से बचाया जा सकता है। सांप आमतौर पर रात में सक्रिय होते हैं।

रात में बाहर निकलते समय विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि जब वे भारी घास या लकड़ी का सामान ढोकर ले जा रहे हों तो पहले यह सुनिश्चित करें कि वहां अंदर सांप तो नहीं है। लोगों को स्थानीय सांपों की प्रजातियों के बारे में जानना और उन्हें पहचानना चाहिए ताकि आप संकट की स्थिति में मेडिकल हेल्प के लिए जल्दी निर्णय ले सकें।

इसी तरह बिना वजह झाड़ियों या घास में नहीं घुसना चाहिए। यदि आप को सांप देखाई दे तो उसे उत्तेजित न करें और न ही उस पर हमला करें। सांप केवल आत्मरक्षा के लिए काटते हैं। यदि सांप ने काट लिया है, तो खुद से इलाज करने की कोशिश न करें, जैसे कि घाव को काटना या चूसना। यह स्थिति को और खराब कर सकता है। खास बात यह भी कि सांप के काटने के लिए कोई घरेलू उपाय या दवा का प्रयोग न करें। डॉक्टर की सलाह और एंटीवेनम (विषरोधी औषधि) का ही उपयोग करें और जितनी जल्दी हो सके त्वरित चिकित्सा सहायता प्राप्त करें।

भारतीय न्याय प्रणाली: अब राष्ट्रीय न्यायिक सेवा के गठन का वक्त.. प्रतिभाशाली न्यायाधीशों को मिलेंगे बेहतर अवसर

लॉबित मुकदमों की बढ़ती संख्या पर एक बार फिर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। बीते एक सितंबर को संपन्न जिला अदालतों के राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ तथा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक स्वर में शीघ्र और सुलभ न्याय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने न्यायिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती प्रक्रिया की पैरवी करते हुए कहा कि अब समय आ गया है, जब क्षेत्रवाद और राज्य केंद्रित चयन की संकीर्ण सीमाओं से आगे बढ़ा जाए।

पहले भी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सुझाव आते रहे हैं। विधि आयोग वर्ष 1958 और वर्ष 1978 में दो अलग-अलग संस्तुतियों के माध्यम से इसके लिए सुझाव दे चुका है। आयोग का मत था कि इससे अदालतों में लॉबित मुकदमों के समयबद्ध निस्तारण में आसानी होगी, न्यायिक-संरचना अधिक पारदर्शी तथा क्रमबद्ध हो जाएगी और उसके परिणामस्वरूप मुकदमों का तेजी से निपटारा होगा और आम लोगों का उन पर भरोसा बढ़ेगा। संसद की %लोक शिकायत, कानून तथा न्याय की स्थायी समिति% ने भी वर्ष 2006 में इस विषय पर सुझाव दिया था। इसके अलावा, इस समिति ने एक मसौदा भी तैयार किया था, किंतु वह आगे नहीं बढ़ पाया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई मौके पर

इस संबंध में सुझाव और निर्देश दिया था। सबसे पहले वर्ष 1992 में ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया था। उसके बाद फिर वर्ष 1993 में इस पर जरूरी पहल करने की जिम्मेदारी सरकार के विवेक पर छोड़ दी गई। फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय का स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायाधीशों के चयन के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था के निर्माण करने का सुझाव दिया, किंतु अब तक इस पर कोई ठोस पहल नहीं की जा सकी है। लोकशाही में उसके सभी उपांगों की विश्वसनीयता उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। अदालतों के मामले में तो यह अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह उनकी एकमात्र पूंजी होती है। जनता के बीच उनकी साख और आम लोगों के मन में उसके प्रति सम्मान ही उसकी ताकत की गंगात्री होती है। इसलिए उन्हें अपेक्षाकृत अधिक सजा रहने की जरूरत होती है। मुकदमों का अंबार, उनके निस्तारण में देरी तथा पारदर्शिता से जुड़ी अपेक्षाएं न्यायपालिका की साख को सबसे अधिक प्रभावित कर रही हैं। पारदर्शिता के प्रति आग्रही समाज में गैर-जरूरी गोपनीयता कई बार अविश्वास के काल्पनिक कारणों तथा आधारों को तैयार करने की पृष्ठभूमि बनाता है। कॉलेजियम व्यवस्था की गोपनीयता के कारण अब उन पर भी



प्रश्न उठने लगे हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कुछ वर्तमान न्यायाधीशों ने भी उस पर सवाल उठाए हैं। ये सभी तथ्य ऐसे हैं, जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के पक्ष में पर्याप्त आधार तैयार करते हैं। न्यायपालिका के अखिल भारतीय सेवा के पक्ष में यह कहा जा रहा है कि यह पूरे देश के लिए एक ऐसी पारदर्शी चयन प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रतिभाशाली युवाओं को मौका मिलेगा। इसमें समाज के सभी वर्गों तथा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। चूंकि यह चयन राष्ट्रीय स्तर पर होगा, इसलिए इसमें

सबसे अच्छे लोगों के चयन की एक परंपरा विकसित होगी। मुकदमों की बढ़ती संख्या का एक कारण यह भी है कि हमारे यहां न्यायाधीशों की बहुत कमी है। अमेरिका में जहां हर 10 लाख आबादी पर 107 न्यायाधीश हैं, वहीं हमारे यहां इतनी आबादी पर मात्र 21 न्यायाधीशों के पद ही सृजित हैं। अलग-अलग राज्यों में उनके चयन की प्रक्रिया में अक्सर देरी होती रहती है, जिसके कारण कुल 25,246 स्वीकृत पदों के सापेक्ष केवल 19,858 न्यायाधीश ही कार्य कर रहे हैं। नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की रिपोर्ट के

अनुसार, मुकदमों के दायर होने की वर्तमान दर के मुताबिक 2040 में कुल 15 करोड़ मुकदमे लॉबित होंगे, जिनके निस्तारण के लिए 75,000 न्यायाधीशों की जरूरत होगी। विभिन्न राज्य अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन से इस चुनौती से निपटना आसान हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में कहा गया है कि इसके द्वारा चयनित व्यक्ति जिला न्यायाधीशों के समकक्ष होगा। यह पद जब केंद्रीय स्तर पर भरा जाएगा, तो केंद्र सरकार से जरूरी पदों को सृजन और उनकी चयन-प्रक्रिया

को पूरा करने के लिए दबाव बनाना आसान होगा। जिस तरह से अन्य भारतीय सेवाओं के लिए आबादी के अनुपात में पदों का सृजन होता है, उसी तरह यहां पर भी यह काम आसान हो जाएगा और आबादी तथा मुकदमों के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या हो जाने से मुकदमों का बोझ कम होगा।

इस समय न्यायपालिका में चयन के लिए पद्धतियां हैं। जिला अदालतों के लिए लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से चयन होता है। उच्च न्यायालयों के 25 प्रतिशत पद इन न्यायिक अधिकारियों की प्रोन्नति से, जबकि शेष पद अधिवक्तागण में से कॉलेजियम द्वारा भरे जाते हैं। जिला अदालतों के लिए लिखित परीक्षा के माध्यम से न्यायिक सेवा में आने वाले न्यायाधीशों के उच्च न्यायालय तक पहुंचने की संभावना बहुत कम होती है। सुप्रीम कोर्ट तक उनके पहुंचने की तो कल्पना करना भी कठिन है। इन परिस्थितियों में उनके मन में वंचना-बोध पैदा होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि प्रतिभाशाली छात्रों का रुझान इस सेवा की ओर कम होता जा रहा है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के बाद उच्च न्यायालय और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रतिभावान न्यायाधीशों का ऐसा विकल्प उपलब्ध होगा, जो इस संस्था की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों दे सकता है।

विधायक अनुभा मुंजारे ने लालबर्रा अस्पताल में डॉक्टर की नियुक्ति कराई

विधायक मुंजारे के प्रयास से अब हास्पीटल में अतिरिक्त डां. देंगे सेवाएं जनता में हर्ष

लाकेश पंचेश्वर । सिटी चीफ लालबर्रा, बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे द्वारा डॉक्टर की नियुक्ति कराई गई है। उक्ताशय की जानकारी लालबर्रा सरपंच व विधायक प्रतिनिधि अनीस खान एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा के विधायक प्रतिनिधि शैलेश केकती ने संयुक्त रूप से बताया कि जनता कि वर्षों पुरानी मांग पर छेत्रीय विधायक अनुभा मुंजारे द्वारा डॉक्टर की नियुक्ति कराई गई है इस संबंध में विगत दिनों क्षेत्रीय विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे जी के समक्ष जनप्रतिनिधियों ने लालबर्रा तहसील मुख्यालय के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जनहित को ध्यान में रखकर डॉक्टर की व्यवस्था हेतु अपनी मांग रखी थी जिस पर क्षेत्रीय विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे जी द्वारा जिला चिकित्सा



अधिकारी श्री मनोज पांडे से चर्चा कर समस्या से अवगत कराया गया था जिस पर एरूाह द्वारा आदेश जारी करते हुए लालबर्रा अस्पताल हेतु डॉ ऋषभ मेश्राम एवं डॉ विभूति अमूले की नियुक्ति की गई है जिस पर लालबर्रा नगरवासियों सहित ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों ने विधायक अनुभा मुंजारे का आभार जताया है ज्ञात हो कि पूर्व

में विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा भोपाल में विधायक अनुभा मुंजारे ने लालबर्रा अस्पताल की बात दमदारी से रखी थी। लालबर्रा समुयायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की नियुक्ति पर ब्लाक कांग्रेस अध्यक्षगण दमनसिंह राहंगडाले, भाऊराम गडेश्वर,जिला पंचायत विधायक प्रतिनिधि व सरपंच अनीस खान, विधायक प्रतिनिधि

समुयायिक स्वस्थ केंद्र लालबर्रा शैलेश केकती, कन्हैया राहंगडाले, बालकृष्ण बिसेन,लक्ष्मी वघाड़े, सुमेन्द्र पटले,दीपक कावरे, सन्देश सैयाम,विनीता सोनी, नितिन सांखला,अशोक जैन, सुमित स्वामी,मथुरा प्रशाद बिसेन,रूपसिंह उडके,सहित छेत्रवासियो ने हर्ष व्यक्त कर विधायक अनुभा मुंजारे जी का आभार जताया है।

बड़े ही धूमधाम से कजई में मनाया गया पोला पाटन पर्व

पोला पर्व पर घरो घर की गई बैलों की पूजा - आनंद बिसेन

लाकेश पंचेश्वर । सिटी चीफ लालबर्रा, जनपद पंचायत अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कजई में पोला पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया,पोला पर्व पर मिट्टी के बैल और खिलौने की पूजा भी पर्व के दिन की जाती है पोला पर्व पर पकवान ठेठरी,खुरमी जैसे पारम्परिक पकवान बनाये जाते है पोला पर्व किसानो का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है पोला पर्व किसानों और खेतीहार मजदूर के लिए विशेष महत्व रखता है कहा जाता है की बैल किसानो के बेटे की तरह होते है पोला पर्व पर बैल को किसान खासतौर पर पूजा करते है खेती किसानी में बैलो का सबसे अहम काम होता है पोला पर्व पर किसान बैलो की पूजा कर उनके प्रति सम्मान जताते है मिडिया से चर्चा करते हुए ग्राम पंचायत कजई सरपंच श्री आनंद बिसेन ने कहा कि पोला पर पर



प्रत्येक किसान अपने अपने बैलों को सजाकर बाजे गाजे के साथ अपने अपने घरों से निकलने तथा श्री हनुमान मंदिर में पहुंचकर सर्वप्रथम पूजा अर्चना करें तत्पश्चात हाइवे रोड़ पर पानी टंकी के पास आखर चौक लेकर पहुंचे जहां पर सभी लोगों ने बैलों व बैल मालिक को तिलक लगाएं

तथा किसानों ने पोला पर्व को लेकर दोहे भी बोले जिससे उपस्थित लोग आनंदित हुए तथा पूजा अर्चना कर बैलो को दौड़ाया भी गया जिसके बाद किसानो द्वारा बैलो को घरो घर लेकर जाकर उन्हें मिस्टान खिलाकर पूजा अर्चना की गई है,जहां पर ग्राम के सभी लोग मौजूद रहे।

आर्थिक तंगी से जूझ रहे अतिथि शिक्षकों ने निकाली स्वयं की अर्थी यात्रा

5 को भोपाल में होगा प्रदर्शन



भगवान दास बैरागी।सिटी चीफ शाजापुर, नियमितीकरण की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्षरत अतिथि शिक्षक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और इसीको लेकर उन्होंने अपनी ही अर्ुथी यात्रा निकाल दी। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शाजापुर जिले के अतिथि शिक्षकों ने सोमवार को शाजापुर में अर्थी यात्रा निकाली। काधे पर अर्थी लेकर अतिथि शिक्षक शहर के महपुरा चौराहा, नदी चौराहा, किला रोड, छोटा चौक, बड़ा चौक, नई सडक होते

हुए बस स्टैंड पहुंचे जहां नारेबाजी कर अर्थी का अंतिम संस्कार किया गया। संघ के जिलाध्यक्ष आशीष शर्मा ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा महापंचायत बुलाकर अतिथि शिक्षकों से किए गए वादों को पूरा नहीं किए जाने से प्रदेशभर के अतिथि शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है और इसीको लेकर शाजापुर जिला मुख्यालय पर अतिथि शिक्षकों के द्वारा अर्थी यात्रा निकाली गई है। शर्मा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के द्वारा



प्रदेशभर के अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई गई थी जिसमें उन्होंने कई घोषणाएं की थी, लेकिन उक्त घोषणाओं को आज तक पूरा नहीं किया गया है। वहीं अब तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है और प्रमोशन आदि नीति के नाम पर अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया गया है। चुनाव के दौरान भी कई वादे किए गए, यहां तक कि डॉ मोहन यादव ने विधायक रहते हुए स्वयं मंत्र शासन को पत्र लिखकर अतिथि शिक्षकों को नियमित

किए जाने की मांग की, लेकिन अब जबकि वह स्वयं मुख्यमंत्री हैं तो अतिथि शिक्षकों को हटाने पर तुले हुए हैं। 5 सितंबर को पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षक मुख्यमंत्री से मिलने भोपाल जाएंगे। शर्मा ने बताया कि शासन से मांग है कि अतिथि शिक्षकों का 12 माह अनुबंध विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जाए। साथ ही जो घोषणाएं की गई थी उन्हें लागू किया जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक मौजूद थे।

पालकी में सवार होकर शाही ठाठ-बाट से निकले नीलकण्ठेश्वर महादेव भक्तों ने पूजन कर मांगी सुख-समृद्धि

भगवान दास बैरागी ।सिटी चीफ शाजापुर, फूलों से सजी पालकी में सवार होकर नीलकण्ठेश्वर महादेव शाही ठाठ-बाट से भक्तों को दर्शन देने सोमवार को उनके द्वार पहुंचे। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हाट मैदान के गिरासिया घाट स्थित बाबा नीलकण्ठेश्वर शाही ठाठ-बाट से नगर भ्रमण पर निकले। सवारी में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, कालिया नाग मर्दन लीला, श्रीकृष्ण विवाह आदि झांकियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही। वहीं झाबुआ की भगोरिया नृत्य मंडली सदस्यों के



नृत्य ने भी खुब सराहना बटोरी। इसीके साथ बैंड कलाकारों ने

शिव धुन बजाकर पूरे क्षेत्र को शिव के रंग में रंग दिया। सवारी

मंदिर प्रांगण से विशेष पूजा के बाद शाम लगभग 6 बजे रवाना हुई जो बंसी टॉकीज, नदी चौराहा, महपुरा चौराहा, धौबी चौराहा, एबी रोड, ब्रज बिहार कालोनी, नहर चौराहा, स्टेशन रोड, गंगा मार्केट, आदर्श कालोनी, टंकी चौराहा, शास्त्री मार्ग से होती हुई पुनः मंदिर पहुंचकर सर्पन हुई। सवारी मार्ग पर बाबा नीलकण्ठ के दर्शन के लिए जहां भक्त पलक के बिलछाए इंतजार करते दिखाई दिए तो वहीं भोले के स्वागत को लेकर सवारी मार्ग पर जगह-जगह मंचा लगाकर पुष्पवर्षा कर बाबा का अभिनंदन किया गया।

यशपाल सिंह जाट ।सिटी चीफ अनूपपुर, मध्य प्रदेश के अनूपपुर में एसपी ने कानून व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए बड़ा फेरबदल किया है। तीन उप निरीक्षक, दो सहायक उप निरीक्षक और एक आरक्षक का तबदला कर दिया गया है। नवीन पदस्थापना के आदेश जारी किये हैं। पुलिस अधीक्षक मोती उर् रहमान ने प्रशासनिक दृष्टि से की गई पदस्थापना में उपनिरीक्षक संजय खलको को कोतवाली अनूपपुर से थाना करनपठार प्रभारी, कार्यवाहक उपनिरीक्षक अजय टेकाम को थाना करनपठार



से कोतवाली अनूपपुर, कार्यवाहक उपनिरीक्षक अमरलाल यादव को थाना जैतहरी से पुलिस सहायक केन्द्र वेंकटनगर प्रभारी बनाया है। कार्यवाहक सहायक उपनिरीक्षक सुरेश अहिरवार को पुलिस लाइन अनूपपुर से वेंकटनगर चौकी,

कार्यवाहक सहायक उपनिरीक्षक अरविंद राय को पुलिस लाइन अनूपपुर से वेंकटनगर चौकी और आरक्षक चालक गुरुप्रसाद चतुर्वेदी को पुलिस लाइन से महिला थाना अनूपपुर में पदस्थ कर दिया।

बैठक में मूर्ति निर्माताओं पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण अनुकूल मूर्ति निर्माण की अपील की गई व समझाइए दी गई

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना में एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन

उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ सतना, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी श्री एस.पी. झा के दिशा निर्देशन पर एवं प्रयोगशाला प्रभारी डॉ राहुल द्विवेदी के मार्गदर्शन में गठित टीम विनोद तिवारी व राजकुमार मिश्रा द्वारा गणेश दुर्गा मूर्ति निर्माण एवं विसर्जन के संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार सतना जिला एवं मैहर जिले में विभिन्न मूर्ति निर्माता के यहां जाकर पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण अनुकूल मूर्ति निर्माण की अपील की गई व समझाइए दी गई। श्लासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उवेहरा में संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें राजकुमार मिश्रा द्वारा गणेश दुर्गा मूर्ति निर्माण व



विसर्जन सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध एवं पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई एवं गणेश/दुर्गा विसर्जन को लेकर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा

एक विस्तृत गाइड लाइन जारी की गयी है। इस गाइड लाइन में मूर्तिकारों और इसके विक्रेताओं को प्रदूषण को लेकर सजग रहने के लिये कहा गया है। गाइड लाइन

के अनुसार मूर्तियों का निर्माण ऐसे वस्तुओं से किया जाय, जो आसानी से पानी में विघटित हो सके और प्रदूषण को न बढ़ाये। मूर्ति निर्माण मिट्टी एवं प्राकृतिक

वस्तुओं से किया जावे एवं सजावट हेतु प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाय। आम नागरिकों के लिये भी गाइड लाइन में पी.ओ.पी. से बनी मूर्तियों को नदी, तालाब, घाट में विसर्जित नहीं करना है। इसे सिर्फ उन्हीं जगहों पर विसर्जित करना चाहिये जिसे प्रशासन की ओर से चिन्हित कृत्रिम कुण्डों का निर्माण प्रशासन द्वारा जिस स्तर पर किया गया है वहीं करना चाहिये। विसर्जन के प्रहले सजावटी सामग्री अलग कर लेना चाहिए नदियों व अन्य जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने का दायित्व आम आदमी का ही है। धार्मिक कर्मकांडों से प्ररूषित होती नदियों के बचाव में प्रत्येक जागरूक व्यक्ति को आगे आना होगा। इसके लिए धार्मिक

कर्मकांडों में इको-फ्रेंडली यानी प्रकृति मित्र तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। जिसके तहत मूर्तियों को बनाते समय केवल मिट्टी का ही प्रयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार की विषैली धातुओं व प्लास्टिक के उपयोग से बनी मूर्तियां अंततः पर्यावरण के प्रदूषण का कारण बनती हैं।प्लास्टर आफ पेरिस की जगह पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक पदार्थों जैसे मिट्टी, चंदन का की लकड़ी से बनी गणपति मूर्ति को अपनाकर भी हम जलीय जीवन को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अगर हम चाहें तो एक ही गणपति प्रतिमा का कई वर्षों तक उपयोग कर सकते हैं और इसे विसर्जित करने के जगह दूसरी छोटी प्रतिमाओं को विसर्जित कर सकते हैं। इको

फेन्डली प्रतिमा का उपयोग करके ये ऐसी प्रतिमायें होती हैं जो आसानी से पानी में घुल जाती हैं। ऐसी मूर्तियों को खरीदकर जिनमें कृत्रिम पेंट के जगह हल्दी तथा अन्य प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंगों का उपयोग किया गया हो। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना पर्यावरण संरक्षण हेतु नुक्कड़ नाटक संगोष्ठी एवं सेमिनार प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम किए जाते हैं सभी आम नागरिकों से मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना अपील करता है पर्यावरण संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान देकर स्वच्छ सतना स्वच्छ मैहर हो अपना क्लीन सिटी ग्रीन सिटी बनाने में अपना योगदान प्रदान करें।

भक्तिभाव से हुई दादा गुरुदेव की पूजा

कल्पसूत्र चल समारोह आज



शाजापुर, श्वेताम्बर जैनसमाज के आठ दिवसीय पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का आयोजन ओसवालसेरी स्थित मालवरत्न परम पूज्य जैनाचार्य श्रीमद् विजय वीररत्न सुरीश्वरजी महाराजा की शुभप्रेरणा से निर्मित चौबीस जिनालयधाम में धूमधाम से किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं तप-आराधना के कार्यक्रमों का लाभ समाजजन ले रहे हैं। मीडिया प्रभारी मंगल नाहर ने बताया कि स्थानीय ओसवालसेरी स्थित जैन उपाश्रय में आयोजित पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व के तीसरे दिवस सोमवार सुबह वीर सैनिक पूजन सेठ व पार्थ पारिख ने अष्टानिका प्रवचन के दौरान बताया कि अन्य स्थानों पर किए गए पाप तीर्थ स्थानों पर जाकर धुल जाते हैं,

लेकिन तीर्थ स्थान पर किए गए पापों का क्षय होना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए तीर्थ क्षेत्र में जाने पर शुद्ध मन से प्रभु की आराधना के साथ रात्रि भोजन, जमीकंद, भक्षण, अब्रम्हचर्य तथा अभक्ष भक्षण आदि चीजों का त्याग अवश्य ही करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने श्रावक के 11 वार्षिक कर्तव्य संघ पूजा, साधर्मिक भक्ति, यात्रा त्रिक, स्नात्र महोत्सव, देव-द्रव्य वृद्धि, महापूजा, रात्रि जागरण, श्रुत भक्ति, उद्यापन, तीर्थ प्रभावना तथा आलोचना सहित जैन साधु के समान एक दिन का जीवन अर्थात 84 लाख जीवयोनि को अभयदान देने वाले पौषध व्रत के संबंध में विस्तारपूर्वक समझाया। इसके पश्चात दोपहर 2 बजे ओसवाल सेरी दादावाड़ी

में स्व कैलाशचन्द्रजी बरडिया जैन की स्मृति में कामेश बरडिया जैन की तरफ से दादा गुरुदेव की पूजा का धार्मिक आयोजन सम्पन्न हुआ। वहीं रात्रि के समय प्रभु भक्ति की गई व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कल्पसूत्र का चल समारोह आज- नाहर ने बताया कि पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व के चतुर्थ दिवस आज मंगलवार को सुबह 9 बजे कल्पसूत्र बेहराने के साथ ज्ञानपूजा करके कल्पसूत्र वाचन प्रारंभ किया जाएगा। इसके पश्चात दोपहर 1.30 बजे चौबीस जिनालयधाम से कल्पसूत्र का भव्य चलसमारोह निकाला जाएगा जो शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर पुनः मंदिर पहुंचेगा।

विमुक्त दिवस पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन

आयोजित संगोष्ठी में विभागीय योजनाओं, रोजगार मूलक योजना की संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ अनुपपुर, 31 अगस्त विमुक्ति दिवस का आयोजन जिले में विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में विमुक्ति दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहायक संचालक श्रीमती मंजुला सेंद्रे, निरीक्षक सुश्री निकिता भलावी, विमुक्त घुमंतू एवं अर्धघुमंतु समिति के सदस्य श्री काशीराम बंजारा, श्री बृजराज जोगी, श्री ईश्वर सिंह नायक, नवल नायक एवं समुदाय के अन्य सदस्य तथा कर्मचारी उपस्थित रहे। आयोजित संगोष्ठी में विभागीय योजनाओं की तथा रोजगार



मूलक योजना की संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। विमुक्त जनजाति समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा सहायक संचालक को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। भोपाल में आयोजित

विमुक्ति दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया एवं विमुक्त छात्रावास में अध्ययनरत छात्रों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार वितरण किया गया।

कटनी में निकाली गयी अर्थी यात्रा

मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

सुनील यादव । सिटी चीफ कटनी, कटनी में अतिथि शिक्षकों ने शासन-प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. तमाम मांगों को लेकर अतिथि शिक्षकों ने अर्थी यात्रा निकाली और कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। जहां उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों ने बताया कि अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर विभागीय पात्रता परीक्षा आयोजित कर नियमित शिक्षक बनाया जाए। इसके साथ ही शिक्षक भर्ती में 20 प्रतिशत अंक का बोनस दिया जाए। इन सभी मांगों को लेकर जिले भर के अतिथि शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे। जहां से उन्होंने कलेक्टर कार्यालय तक अर्थी यात्रा निकाली। इस दौरान अतिथि शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी की और विरोध जताया।



इसके बाद अतिथि शिक्षकों मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकों की मौजूदगी रही। अतिथि शिक्षकों ने यह भी बताया कि आज ही के दिन 2 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल में प्रदेशभर के अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें उन्होंने कई घोषणाएं की थी। पूर्व सीएम द्वारा की

घोषणाओं को राज्य सरकार द्वारा आज तक पूरा नहीं किया गया है। घोषणाएं पूरी न होने पर आज 2 सितंबर 2024 को जिले के समस्त अतिथि शिक्षकों ने एकत्रित होकर अर्थी यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं 4 सितंबर तक अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 5 सितंबर को पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षक भोपाल में संघर्ष करेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे।

पोस्ट ऑफिस में 72.36 लाख के गबन मामले में मेड़ता रोड उप डाकघर पहुंची सीबीआई, शुरू की पूछताछ व जांच

एजाज अहमद उस्मानी । सिटी चीफ मेड़तारोड, मेड़तारोड पोस्ट ऑफिस में 72 लाख 36 हजार 44 रुपए की राशि के गबन के मामले में सोमवार को सीबीआई टीम मेड़ता रोड पहुंची। इस संबंध में डाक अधीक्षक नागौर ने उप डाकपाल मेहरूदीन के खिलाफ जोधपुर सीबीआई में मामला दर्ज करवाया था। सीबीआई टीम ने पीड़ित खाताधारकों से पूछताछ के साथ मामले की जांच की। जानकारी के अनुसार मेड़तारोड पोस्ट ऑफिस में 27 खाताधारकों के उपडाकपाल मेहरूदीन ने 2 अगस्त 2022 से 19 अप्रैल 2024 तक 62

लाख 22 हजार 44 का गबन कर लिया तथा अस्थायी रूप से 10 लाख 14 हजार की हेराफेरी की। कुल 72 लाख 36 हजार 44 का गबन समझे आया है। आरोपी ने खाताधारकों की ओर से जमा व निकासी राशि की पासबुक में तो एंट्री कर दी थी लेकिन खाताधारक के खाते में रकम का कोई उल्लेख नहीं किया था। उप डाकपाल ने फर्जी निकासी प्रपत्र तैयार कर राशि का गबन किया गया था। मई माह में मामला उजागर होने के बाद जांच में यह भी सामने आया था कि जब खाताधारक भुगतान के लिए डाकघर गए तो संदिग्ध लोकसेवक



उपडाकपाल ने ब्याज की राशि जोड़कर जमा राशि को बढ़ा दिया था। इस तरह से उप डाकपाल मेहरूदीन सरकारी पैसे का अस्थायी रूप से गलत तरीके से दुरुपयोग कर रहा। इस संबंध में डाक अधीक्षक नागौर रामअवतार सोनी द्वारा जोधपुर सीबीआई में मामला दर्ज करवाया गया था। सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच निरीक्षक मदनलाल बेनीवाल को सौंपी है। मेड़ता रोड पोस्ट ऑफिस में सब पोस्टमास्टर द्वारा किए गए लाखों रुपए के चोटाले मामले में आज सीबीआई टीम जोधपुर एसीबी ब्रांच इंस्पेक्टर मदनलाल बेनीवाल के

नेतृत्व में मेड़ता रोड पहुंची। सीबीआई की यह टीम इन दिनों में 26 उपभोक्ताओं से पूछताछ कर आरोपी सब पोस्टमास्टर मेहरूदीन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगी। आपको बता दें कि नागौर पोस्ट ऑफिस अधीक्षक राम अवतार सोनी ने अधीनस्थ कर्मचारी मेड़ता रोड सब पोस्टमास्टर मेहरूदीन के खिलाफ जोधपुर सीबीआई में मामला दर्ज कराया था। मेड़ता रोड पोस्ट ऑफिस में 21 से अधिक खाताधारकों के बचत खाते से 70 लाख से अधिक की राशि का गबन किया गया था।

14 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन

नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बैठक सम्पन्न

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ अनुपपुर, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 14 सितम्बर 2024 को सम्पूर्ण प्रदेश के जिला एवं तहसील सिविल न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उक्त नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन एवं पक्षकारों के मध्य प्रकरणों के आपसी सुलह व समझौते के आधार पर निराकरण हेतु शनिवार 31 अगस्त को जिला न्यायालय के अधिवक्ता बार कक्ष में समस्त अधिवक्तागण के साथ बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री पी.सी. गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की



सचिव श्रीमती मोनिका आध्या, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री नरेन्द्र पटेल, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री पंकज जायसवाल, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती चैनवती ताराम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती पारुल जैन, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलावर सिंह, जिला अधिवक्ता

संघ के अध्यक्ष श्री संतोष सिंह परिहार एवं समस्त अधिवक्तागण उपस्थित रहे। बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पी.सी. गुप्ता द्वारा समस्त अधिवक्तागण से लोक अदालत में सहयोग प्रदान करने एवं अपने-अपने पक्षकारों के साथ अधिक से अधिक प्रीसिटिंग बैठकें आयोजित कर नेशनल लोक अदालत के

माध्यम से अपने प्रकरणों का निराकरण किए जाने हेतु प्रेरित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वैवाहिक प्रकरणों में दोनों पक्षकारों के मध्य नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह व समझौता कराया जाना पुण्य का कार्य माना जाता है। मध्यस्थता व समझौता करने में दोनों पक्ष की जीत होती है।

रवि राठी जनसेवा फाऊंडेशन आयोजित दही हंडी उत्सव

हजारोंच्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते, सिने अभिनेत्री र्स्नेहा उल्लाल देखील उपस्थित होत्या

डॉ संजय चव्हाण । सिटी चीफ मुर्तीजापुर, दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी स्वर्गीय रमेशचंद्र राठी चॅरिटेबल ट्रस्ट तथा रवी राठी जनसेवा फाऊंडेशन आयोजित सार्वजनिक दहीहंडी उत्सवाचा कार्यक्रम मुर्तीजापुर येथील गाडगे महाराज विद्यालयात संपन्न झाला यावेळी अनेक गोविंदा पथके तथा महा विकास आघाडीचे पदाधिकारी उपस्थित होते विदर्भात दहीहंडी उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतो दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी स्व. रमेशचंद्र राठी चॅरिटेबल ट्रस्ट तथा रवी राठी जनसेवा फाऊंडेशन रवी राठी मित्रपरिवार यांच्या वतीने दहीहंडी उत्सवाचे आयोजन मुर्तीजापुर येथील गाडगे महाराज विद्यालयात करण्यात आले होते या कार्यक्रमाला सिने अभिनेत्री स्नेहा उल्लाल यांची प्रमुख उपस्थिती होती सिने अभिनेत्री स्नेहा उल्लाल यांनी मुर्तीजापुर वाशीयांना वंदन करत समाजसेवक रवी राठी यांच्या कार्याची स्तुती केली यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेश संघटक सचिव रवी राठी यांनी आतापर्यंत अनेक युवा युतींना रोजगार उपलब्ध करून दिला त्याचबरोबर त्यांनी संकल्प केला आहे रवि राठी जनसेवा फाऊंडेशनच्या माध्यमातून येणार्या काळात दहा हजार युवक युवतींना रोजगार देण्याचा त्यांनी यावेळी संकल्प केला आहे यावेळी



कार्यक्रमाला मंचकावर प्रमुख उपस्थित अमरावती लोकसभेचे खासदार बळवंत वानखडे, माजी आमदार तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे ज्येष्ठ नेते सहकार नेते भैर्यासाहेब तिडके राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार अकोला जिल्हाध्यक्ष संग्राम भैर्या गावंडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रवादी काँग्रेस आशाताई मिरगे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्यांक प्रदेश उपाध्यक्ष निजाम ईजिनिअर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ओबीसी सेल प्रदेश उपाध्यक्ष इब्राहिम घानीवाला, राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष युवक संदिप जळमकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष सुष्मा कावरे, जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस महिला

आघाडी पूजा काळे, अविनाश देशमुख, राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हा महासचिव आनंद वाणखडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हा उपाध्यक्ष श्रीधर मोरे, परिमल लहाने, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ओबीसी सेल जिल्हा कार्याध्यक्ष विष्णू लोढम,राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी तालुकाध्यक्ष मुर्तीजापुर मंगेश कुकडे, बारिंटाकळी तालुका अध्यक्ष सतिष गावंडे, मुर्तीजापुर काँग्रेस तालुकाध्यक्ष जितेंद्र गुल्हाने,शिवसेना तालुका अध्यक्ष अप्पू तिडके, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शहराध्यक्ष राम कोवडे, काँग्रेस शहर अध्यक्ष शोहेल शेख,राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी महिला आघाडी तालुकाध्यक्ष रंजना सरदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी

युवा जिल्हा उपाध्यक्ष सचिव गावंडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी महिला शहर अध्यक्ष दिपाली देशमुख, राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेल शहर अध्यक्ष विशाल सिरभाते, प्रशांत कडू, उपस्थित होते यावेळी हजारो युवक युवती तरुणी महिला यांनी या दहीहंडी उत्सवामध्ये सहभाग घेतला होता फ्रँड्स ग्रुप धामणगाव या गोविंदा पथकाने दहीहंडी फोडून उत्सव साजरा केला कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आर जे.श्री, आकांक्षा गोमासे यांनी केले यावेळी विविध भागातून आलेल्या गोविंद पथकांनी थरांवर थर लावून दहीहंडी उत्सव संपन्न केला यावेळी हजारो युवक युती तथा नागरिक उपस्थित होते।

सांसद इमरान मसूद ने देवबंद डाक बंगले पर सुनी लोगों की समस्याएं

अधिकारियों को उक्त समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश

गौरव सिंघल । सिटी चीफ सहारनपुर। देवबंद, सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने आज देवबंद डाक बंगले पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। सांसद इमरान मसूद ने लोगों की समस्या सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को उक्त समस्याओं का समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान सांसद इमरान मसूद ने कहा कि जनता की समस्याओं समाधान कराना उनके लिए सर्वोपरि है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनहित के काम प्राथमिकता के तौर पर किए जाए। सांसद इमरान मसूद बोले जनसमस्याओं की अन्वेष्टो किसी भी क्रीमत पर बर्दाश्त नहीं की



जाएगी। सांसद इमरान मसूद ने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न व शोषण किसी भी क्रीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा की

अधिकारी जनता के सेवक के रूप में कार्य करे और जनता को त्वरित न्याय दिलाये। इस दौरान सभासद सय्यद हारिस, काँग्रेस नेता राहत खलील, अब्दुल कादिर

अंसारी, मूसा चौधरी, अहमद गौड़, परवेज़ गौड़ पप्पू, डॉ रागिब अंजुम, यूसफ़, खलील, भूरा चौधरी, कलीम चौधरी आदि उपस्थित रहे।

मीरापुर उपचुनाव में रालोद की होगी जीत : सांसद चंदन चौहान

सुरेंद्र सिंहल, वरिष्ठ पत्रकार. मीरापुर (मुजफ्फरनगर), रालोद सांसद चंदन सिंह चौहान ने आज दावा किया कि मीरापुर विधानसभा के शीघ्र होने वाले उपचुनाव में रालोद उम्मीदवार की जीत तय है। उन्होंने कहा कि मीरापुर ऐसी सीट है जिस पर उनके दादा चौधरी नारायण सिंह पूर्व उपमुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पिता संजय चौहान और वह स्वयं विधायक चुने जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के वक्त वह मीरापुर से विधायक थे। उन्होंने सांसद चुने जाने पर विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। नवंबर में उपचुनाव होने की संभावना है। इस सीट पर रालोद का प्रभाव है और साथ ही उनके अपने परिवार का मजबूत जनाधार है। पार्टी



अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी उम्मीदवार का चयन करेंगे। यदि याशिका चौहान को मौका दिया जाता है तो भाजपा-रालोद मिलकर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और ऐसी कोई वजह नहीं जो याशिका चौहान

भारी मतों से चुनाव न जीते। चंदन चौहान ने कहा कि वह लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं और हजारों लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं और समाधान का प्रयास करते हैं।

पेस्टीसाइड विक्रेता ने कंपनी के एक एमआर पर दुकान में रखा चार लाख रुपए से भरा बैग चोरी करने का लगाया आरोप

पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की शुरू की जांच

गौरव सिंहल । सिटी चीफ देवबंद (सहारनपुर)। पेस्टीसाइड विक्रेता ने कंपनी के एक एमआर पर दुकान में रखा चार लाख रुपए से भरा बैग चोरी कर लेने का आरोप लगाया है। गांव कुलसत निवासी गोविंद त्यागी ने पुलिस को बताया कि देवबंद में नूरपुर तिराहे पर उसकी पेस्टीसाइड की दुकान है। बीते दिन वह अपने घर से दवाई का भुगतान करने के लिए बैग में चार लाख रुपए लेकर आया था। बैग को उसने दुकान में बने काउंटर के अंदर रख दिया था। कुछ देर बाद ही कंपनी का एक एमआर दुकान पर आया जो करीब तीन घंटे वहां रहा। दोपहर में जब वह खाना लेने के लिए बाहर गया तो आरोप है कि



एमआर ने मौका पाकर बैग काउंटर से चोरी कर लिया और चला गया। जब वह दुकान पर पहुंचा तो बैग उसे वहां नहीं मिला। जब उसने एमआर को फोन किया तो उसने संतोषजनक

जवाब नहीं दिया। गोविंद त्यागी ने एमआर पर रूपयों का बैग चोरी करने का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच कराई जा रही है।

स्टेट हाईवे पर से उखड़े रैडियम रिफ्रैक्टर सड़क पर निकली नुकीली कीलों के कारण राजगीर परेशान



एजाज अहमद उस्मानी । सिटी चीफ मेड़ता रोड, मेड़ता रोड में मेड़ता सिटी से लेकर मुंडवा तक बनने वाले स्टेट हाईवे पर यातायात सुरक्षित बनाने के लिए लगाए गए रैडियम रिफ्रैक्टर अब मुख्य सड़क से पूरी तरह अदालत हो चुके हैं। इन रैडियम रिफ्लेक्टर के सड़क से निकल जाने के कारण सड़क पर ठोकी नुकीली कीलें राहगीरों के लिए अब जी का जंजाल बनने लगी हैं। सड़क पर निकली हुई इन नुकीली कीलों के कारण कई

वाहन चालकों के टायरों में पंचर हो जाते हैं तथा कई पैदल चलने वाली राहगीर ठोकर खाकर भी गिर जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां पर जो रिफ्लेक्टर लगाए गए थे वह सही तरीके से नहीं लगाए गए हैं जिसका खामियाजा इस सड़क पर चलने वाली राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ठेकेदार द्वारा बनाई गई सड़क इस बात को दर्शाती है कि इस सड़क निर्माण में पूर्ण रूप से घटिया

सामग्री का इस्तेमाल किया गया है जिसके कारण ही सड़क पर लगे रैडियम रिफ्लेक्टर कुछ ही दिनों में टूट कर निकल गए हैं। इतना ही नहीं यह रिफ्लेक्टर जारोड़ा पुलिस से लेकर मेड़ता रोड में जहां तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है वहां तक पूरी तरह से निकल चुके हैं। स्थानीय लोगों ने वाहन सड़क पर से निकले हुए रिफ्लेक्टरों को वापस लगाने तथा निकली हुई कीलो को सड़क पर से निकलने की मांग की है।

भाकियू महाशक्ति के तत्वाधान में मासिक पंचायत का हुआ आयोजन

एसडीएम देवबंद को सौंपा गया 11 सूत्रीय मांग पत्र

गौरव सिंहल । सिटी चीफ सहारनपुर, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के तत्वधान में तहसील मासिक पंचायत का आयोजन किया गया। जिसमें किसान, मजदूर की समस्याओं को लेकर विचार- विमर्श हुआ और उनको तत्काल हल करने के संबंध में एसडीएम देवबंद अंकुर वर्मा को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। पंचायत को संबोधित करते हुए पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष प्रियदीप ने कहा बीते शुक्रवार को क्षेत्र में एक बड़ी घटना होने से बची जिसमें स्कूल वाहन की बस के टायर निकल गए। जिससे एक बड़ा हादसा होते-होते बचा। प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द सभी स्कूल वाहनों की बारीकी से जांच हो। प्रदेश मुख्य महासचिव अरविंद त्यागी ने कहा कि सरकार द्वारा 14 दिन के अंदर भुगतान करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है पर धरातल पर बिल्कुल भी यह कार्य नहीं हो रहा है। संगठन मांग करता है जल्द से जल्द करना भुगतान 14



दिनों के अंदर सुनिश्चित किया जाए। तहसील अध्यक्ष अरविंद शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में डेंगू का प्रकोप फैल

सकता है अतः बचाव के तौर पर सभी स्कूलों और गांवों में छिड़काव होना अति आवश्यक है। कार्यक्रम का संचालन युवा

जिलाध्यक्ष हिमांशु गुर्जर ने किया। इस दौरान पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष प्रियदीप, प्रदेश मुख्य महासचिव अरविंद त्यागी, जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार, वरिष्ठ जिला प्रभारी रविंद्र त्यागी, नगर अध्यक्ष बालेंद्र, युवा जिला अध्यक्ष गुर्जर, युवा जिला महासचिव विश्वदीप सिंह, तहसील अध्यक्ष अरविन्द शर्मा, युवा तहसील अध्यक्ष श्रीकांत, तहसील उपाध्यक्ष आदेश त्यागी,ब्लाक महासचिव रविंद्र राणा, ब्लॉक उपाध्यक्ष रमेश राणा,युवा ब्लॉक महामंत्री अंशुल,ब्लॉक सचिव निंदीप त्यागी, ग्राम अध्यक्ष कंटू त्यागी, शकील अहमद जिला उपाध्यक्ष, प्रदीप उपाध्याय ब्लॉक सचिव पहल सिंह, श्रीकांत, आदेश कुमार, कंवरपाल, चंद्रकांत शर्मा, अजय तहसील महासचिव, विपिन ब्लॉक महामंत्री, प्रभात जिला उपाध्यक्ष, मुकेश ब्लॉक उपाध्यक्ष, सत्येंद्र ग्राम उपाध्यक्ष, मनोज त्यागी ब्लॉक सचिव, मोहित चौहान, राहुल त्यागी आदि सैकड़ों किसान मौजूद रहे।

सड़कों पर विचरण करने वाले गौवंश पर लगाये जाएं रैडियम बेल्ट

लावारिस कुत्तों को बस्तियों से बाहर किया जाए

राजगढ़ सहकारी समितियों का अंकेक्षण होगा सीएम हेल्पाइन के निराकरण में लापरवाही पर होगी कार्रवाई - कलेक्टर



कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने सड़कों पर विचरण करने वाले गौवंश को दुर्घटना से बचाने के लिए उनके गले में रैडियम बेल्ट अथवा उनके सींगों में रैडियम पट्टी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों के गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों द्वारा गायों के नवजात बछड़ों एवं राहगीरों पर हमला करने संबंधी शिकायतें मिल रही हैं, लावारिस कुत्तों को बस्तियों से बाहर किया जाए। सोमवार को आयोजित समयावधि अंकित पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में लम्बित शिकायतों के निराकरण में ढिलाई के बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए।बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकरी जिला पंचायत श्री महीप किशोर तेजस्वी एवं अपर कलेक्टर श्री शिव प्रसाद मंडराह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

जिले में सहकारी समितियों में अनियमितता की मिल रही जानकारी को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने सभी सहकारी समितियों का रोस्टर बनाकर ऑडिट किए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि ऑडिट में सोसाइटी को बैंक द्वारा दिया गया ऋण एवं सोसायटी द्वारा हितग्राही को दिए गए ऋण की जांच की जाए। साथ ही समितियों के खातों का भी ऑडिट किया जाए। बैठक में कलेक्टर ने जिले की समस्त पीएचसी एवं सीएचसी स्वास्थ्य संस्थाओं में पर्याप्त दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थाओं में ओपीडी ऑनलाईन दर्ज हो। कलेक्टर ने कहा कि जिन शासकीय संस्थाओं में फर्स्ट एड किट रखे जाने के निर्देश हैं वहां कर्मचारियों को फर्स्ट एड किट में रखी दवाइयों

के सम्बंध में समुचित जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने मुख्य मंत्री कुषक जीवन कल्याण योजना अंतर्गत लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही अज्ञात वाहनों से सड़क दुर्घटना के मामलों में भी प्रभावितों को भी आर्थिक सहायता देने के प्रकरण लम्बित नहीं रखे जाने के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि युवाओं के लिए ड्राईविंग लाइसेंस बनाने के लिए कैम्प आयोजित किए जाएं। सवारी वाहन चालकों का अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों का आवश्यक रूप से ई-केवायसी होना सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिली तो उसकी जवाबदारी

सम्बन्धित छात्रावास के अधीक्षक की होगी। शिक्षकों की अतिशेष होने सम्बंधी काउंसलिंग में अनियमितता की जानकारी मिलने पर कलेक्टर द्वारा सीईओ जिला पंचायत को काउंसलिंग की जांच करने के लिए निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने भू-अभिलेख अधीक्षक को निष्क्रिय खसरों की जानकारी प्रस्तुत किए जाने के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा ब्यावरा की सब्जी मंडी की भूमि का सीमांकन करने के लिए भी कहा गया। पशु चिकित्सा विभाग के भृत्य श्री बाबू लाल जाटव का जीपीएफ पार्ट फाईनल स्वीकृत नहीं होने की शिकायत पर कोषालय एवं पशु चिकित्सा विभाग के सम्बंधित लिपिक की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए। बैठक में मलेरिया, डेंगू जैसी वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने, जल भराव नहीं होने देने एवं पानी के रूकने वाले स्थानों पर जला ऑइल का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि इन बीमारियों से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने इस सम्बंध में स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए जागरूक करने की बात भी कही।

कलेक्ट्रेट परिसर में चलाया गया सफाई अभियान, परिसर की करायी गई साफ-सफाई

गुना कलेक्टर द्वारा स्वयं एवं कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों के साथ किया गया श्रमदान कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह ने निर्देशानुसार जिले में साफ-सफाई का नवाचार सतत जारी है। इसी क्रम में आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर में साफ-सफाई अभियान चलाकर पेड़, पोथों की छटाई का कार्य किया गया, जिसमें कलेक्ट्रेट के विभिन्न



अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा स्वयं श्रमदान कर सफाई अभियान में अपनी सहभागिता की गई। आज इस

अभियान के दौरान कलेक्टर डॉ. सिंह द्वारा स्वयं श्रमदान कर पेड़ पोथों की छटाई की गई। इस दौरान नगर

पालिका, उद्यानिकी विभाग की टीम द्वारा सहयोग किया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री अखिलेश जैन, अनुविभागीय अधिकारी गुना श्रीमति शिवानी पाण्डे, अनुविभागीय अधिकारी आरोन श्री विकास कुमार आनंद, संयुक्त कलेक्टर श्री महेश कुमार बमन्हा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमति जिया फातिमा सहित अन्य अधिकारियों उपस्थित रहे।

सीएम हेल्पलाईन तथा समय सीमा के पत्रों का निराकरण गंभीरता से करें अधिकारी - कलेक्टर

उमरिया .समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने सभी जिला प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण एल-1 स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाए। कोई भी शिकायत अन अटेण्डेंट नही हो । आपने कहा कि जिन विभागों के पास अधिक शिकायते लंबित है वे विभाग अपने अधीनस्थ अमले को भी लगाकर शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण सुनिश्चित कराएं। जिन विभागों में 10 से कम शिकायते हो वे विभाग शत प्रतिशत शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने समय

सीमा के पत्रों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी अधिकारी शासन से प्राप्त निर्देशों का समय सीमा में क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें । इसी तरह न्यायालयीन प्रकरणों तथा सीएम प्रकोष्ठ से प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को उनका निराकरण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, अपर कलेक्टर शिव गोविंद सिंह मरकाम, एसडीएम बांधवगढ रीता डेहरिया, एसडीएम पाली टी आर नाग, एसडीएम मानपुर कमलेश नीरज, डिप्टी कलेक्टर मौनाक्षी इंगले, तहसीलदार बांधवगढ सतीश सोनी सहित जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे ।



केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में, मोदी ने शुरू किया भाजपा का सदस्यता अभियान

पीएम बोले- हमारा संगठन अकेला जो हर 6 साल में चलाता है सदस्यता अभियान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। पार्टी मुख्यालय में आयोजित इस समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री के बाद शाह, नड्डा और राजनाथ सिंह ने भी पार्टी द्वारा जारी किये गए मोबाइल नंबर पर मिस्ट कॉल देकर भाजपा में अपनी सदस्यता का नवीनीकरण किया। पीएम ने इस अभियान को लॉन्च करते हुए कहा कि हमारा देश एक युवा देश है। मेरे सामने 18 से 25 साल के नौजवान हैं जो 2047 के भारत के लिए सबसे बड़ा प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन केवल एक चुनावी मशीन नहीं है कि हम सत्ता के सुख के लिए केवल चुनाव लड़ते हैं। हम वो खाद-पानी हैं जो आप को खपा कर देश के सपनों को संकल्प और संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने की यात्रा में अपने आपको डुबा देते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि भाजपा का सदस्यता अभियान फिर से 'भारत विजय' और 'भाजपा विजय'



अभियान की शुरुआत करेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से संगठन में नयी जान फूँकी जाएगी। भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कहा कि भाजपा एकमात्र राजनीतिक संगठन है जो लोकतांत्रिक तरीके से चलती है और अपने संविधान का पालन करती है। विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा घर से गुप-चुप तरीके से काम नहीं करती है बल्कि पारदर्शी

प्रक्रिया का पालन करती है। नड्डा और शाह दोनों ने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी इस अभियान में 10 करोड़ सदस्यों का मील का पत्थर पार कर लेगी जैसा कि इसने 2014 में पहली बार किया था। भाजपा का सदस्यता अभियान की शुरुआत संगठन पर्व के रूप में की गई है। यह अभियान अगले दो महीनों तक चलेगा तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 25

सितंबर तक दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर तक और तीसरा चरण 16 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। पार्टी अध्यक्ष के मुताबिक तीसरा चरण सक्रिय सदस्य बनने के लिए होगा और पार्टी संविधान के अनुसार सक्रिय सदस्य ही संगठन का चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी पुराने सदस्यों को भी अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करवाना होगा।

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल गिरफ्तार भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की कार्रवाई

कोलकाता। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह गिरफ्तारी भ्रष्टाचार मामले में हुई है। संदीप घोष से सीबीआई ने लगातार कई दिनों तक पूछताछ की। वह अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी मामले में एजेंसी के रडार पर थे। पहले ही उनके और अन्य संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी थी। सीबीआई ने यह जांच अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की शिकायतों के बाद शुरू की। उन्होंने घोष के प्रिंसिपल के रूप में कार्यकाल के दौरान लावारिस शवों की तस्करी, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान में भ्रष्टाचार, निर्माण निविदाओं में भाई-भतीजावाद जैसे वित्तीय कदाचार के अन्य आरोप लगाए थे। दरअसल,



पश्चिम बंगाल के आरजी कर अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर का 9 अगस्त को शव मिला था। आशंका है कि रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर विरोध-प्रदर्शन सोमवार को 25वें दिन भी जारी रहा। हड़ताली डॉक्टर्स आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं, जो अपराध के संदिग्धों में से एक हैं। साथ

ही, संस्थान में वित्तीय घोटाले को लेकर भी वह आरोपी हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद दोनों मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। जांच एजेंसी ने सोमवार को घोष से पूछताछ जारी रखी और फिर देर शाम उन्हें अरेस्ट कर लिया। बता दें कि सीबीआई अस्पताल के पूर्व प्रमुख संदीप घोष से पिछले 15 दिन से पूछताछ कर रही थी और उनका

लाई डिटेक्शन टेस्ट भी किया गया। वहीं, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग को लेकर लालबाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय की सोमवार को घेराबंदी करने का निर्णय लिया। जूनियर सरकारी चिकित्सकों ने ओपीडी में अनिश्चितकालीन काम बंद कर रखा है। डॉक्टर गोयल पर 14 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने आरजी कर अस्पताल मामले के अपराधियों को कठोर सजा देने की मांग के भी नारे लगाए। रैली को पुलिस मुख्यालय तक पहुंचने से रोकने के लिए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए और अवरोधक लगाए गए थे।

स्कूल बस ने लोगों को कुचला पांच छात्रों सहित 11 की मौत

नेशनल डेस्क। चीन के पूर्वी हिस्से में मंगलवार को एक स्कूल बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें पांच छात्रों सहित कुल 11 लोगों की मौत हो गई। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के अनुसार, यह दुर्घटना सुबह 7.27 बजे शांदोंग प्रांत के ताईआन शहर में हुई। रिपोर्ट के अनुसार, जैसे ही स्कूल बस स्कूल के पास पहुंची, चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और बस ने राहगीरों को कुचल दिया। सीसीटीवी के अनुसार, सुबह 7.27 बजे के आसपास, बस जब स्कूल के पास पहुंची, तो चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। बस सड़क के किनारे खड़े अभिभावकों और बच्चों के समूह से टकरा गई। दुर्घटना के बाद, एक अन्य व्यक्ति की स्थिति गंभीर बताई गई है, जबकि 12 अन्य लोगों की हालत स्थिर है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों और वीडियो में घायलों को खून से लथपथ और एक भूरे रंग की बस के पास सड़क पर पड़े हुए देखा जा सकता है। कुछ वीडियो में जमीन पर घुटनों के बल बैठे वस्कों को बच्चों के ऊपर से गुजरते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग पृष्ठभूमि में शोर मचाते हुए सुनाई दे रहे हैं। एक



वीडियो में, एक महिला की आवाज को यह कहते हुए सुना जा सकता है, वे सभी मर चुके हैं, यह बहुत हृदय विदारक है। उसने बताया कि अगर वह वहां होती, तो संभवतः उसकी भी मौत हो जाती, लेकिन सौभाग्यवश वह तेजी से भाग गई। एएफपी ने कई तस्वीरों और वीडियो को शेडोंग

के उस स्कूल से जोड़ने में सक्षम पाया जहां यह घटना हुई थी। सीसीटीवी ने जानकारी दी कि ड्राइवर को स्थानीय पुलिस ने पकड़ लिया है और घटना के कारण की जांच की जा रही है। चीन में इस सप्ताह कई सार्वजनिक स्कूल नए शैक्षणिक वर्ष के लिए फिर से खुल गए हैं।

देश में ढीले सुरक्षा मानकों और अव्यवस्थित ड्राइविंग के कारण अक्सर घातक यातायात दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। जुलाई में, एक अन्य दुर्घटना में चांगशा शहर में एक वाहन पैदल यात्रियों से टकरा गया था, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए थे।

आज विधानसभा में दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश करेगी ममता सरकार

21 दिन में करना होगी जांच, दुष्कर्म के दोषी के लिए मौत की सजा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार मंगलवार को विधानसभा में दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश करेगी। इस विधेयक के मसौदे में दुष्कर्म के दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रस्ताव है, यदि उनके कृत्यों के कारण पीड़िता का मृत्यु हो जाती है या वह बेहोश हो जाती है। इसके अलावा, मसौदे में कहा गया है कि दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के दोषी व्यक्तियों को उनके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। अपराजिता महिला और बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) विधेयक 2024 नाम के इस विधेयक का मकसद महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना है। इसमें दुष्कर्म और यौन अपराधों से जुड़े नए प्रावधान जोड़ने और पुराने प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस मसौदा विधेयक में प्रस्ताव है कि हाल ही में पारित हुए भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 में पश्चिम बंगाल के संदर्भ में संशोधन किया जाए। इसका मकसद सजा को सख्त बनाना और महिलाओं व बच्चों के खिलाफ किए गए गंभीर अपराधों



की तेजी से जांच और मुकदमों का ढांचा तैयार करना है। **महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने का प्रस्ताव-** मसौदा विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि यह विधेयक राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने का प्रस्ताव करता है। यह राज्य की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि वह अपने नागरिकों, खासकर महिलाओं और बच्चों, के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म और यौन अपराधों जैसे घृणित कृत्यों से कानून की पूरी ताकत के साथ निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विधेयक के तहत दुष्कर्म के मामलों की जांच 21 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। जो पहले दो महीने की समय सीमा

से कम है। पिछले महीने राज्य संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के बाद विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में विधेयक को राज्य के कानून मंत्री मलय घटक पेश करेंगे। मसौदा विधेयक का मकसद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धाराओं 64, 66, 70 (1), 71, 72 (1), 73, 124 (1) और 124 (2) में संशोधन करना है। ये धाराएं आमतौर पर दुष्कर्म, दुष्कर्म और हत्या, सामूहिक दुष्कर्म, पुनरावृत्ति करने वाले अपराधियों, पीड़िता की पहचान उजागर करने और एसिड का इस्तेमाल कर चोट पहुंचाने जैसे अपराधों की सजा से संबंधित हैं।

बंगाल सरकार को बड़ा झटका

छात्र समाज के नेता लाहिड़ी की जमानत रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सायन लाहिड़ी को बड़ी राहत देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और जमानत रद्द करने से साफ इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इस महीने की शुरुआत में एक प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म व उसकी हत्या की घटना के विरोध में यह रैली आयोजित की गई थी। कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर से कथित दुष्कर्म और उसकी हत्या के विरोध में देशभर में नाज़ागगी है। वहीं राज्य में तनाव भरे हालात बने हुए हैं। दरअसल, हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को निकाले गए राज्य सचिवालय मार्च के आयोजकों में से एक शख्स को जमानत दे दी थी। इसी आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख किया था प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पाद्रीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा याचिका की सुनवाई हुई।

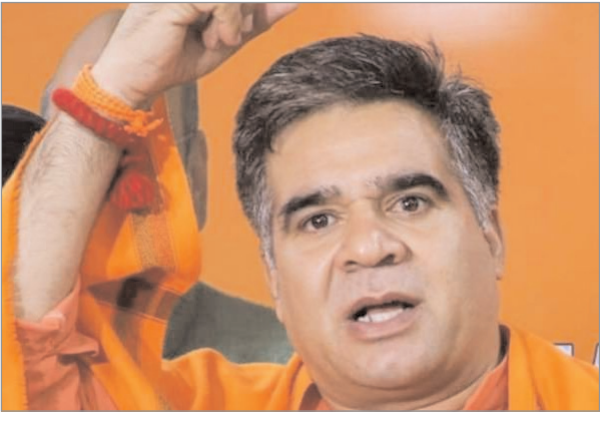


कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी को जमानत दी थी। यह संगठन, एक अपंजीकृत छात्र समूह है। यह उन दो संगठनों में एक है जिसने 27 अगस्त के नबन्ना (राज्य सचिवालय) अभियान का आह्वान किया था। लाहिड़ी को 27 अगस्त की शाम रैली का नेतृत्व करने में सक्रिय भूमिका निभाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा था कि रैली हिंसक हो गई, जिससे सार्वजनिक और निजी

संपत्ति को नुकसान पहुंचा तथा सुरक्षाकर्मियों पर हमले हुए। सायन की मां अंजलि की याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उसे शनिवार अपराह्न दो बजे तक पुलिस हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया था। अंजलि ने अपनी याचिका में बेटे के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने और उसे जमानत देने का अनुरोध किया था। कोलकाता पुलिस ने शनिवार को लाहिड़ी को अपनी हिरासत से रिहा कर दिया।

भाजपा की चौथी लिस्ट जारी, अध्यक्ष रविंद्र रैना नौशेरा से लड़ेंगे

जम्मू। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगमी बढ़ती जा रही है। सोमवार को भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने कुछ और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बीजेपी ने आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। इससे पता चलता है कि जम्मू-कश्मीर भाजपा प्रमुख रविंद्र रैना नौशेरा से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की ओर से जारी इस सूची के मुताबिक, लाल चौक से इंजीनियर एजाजा हुसैन, ईदगाह से आरिफ रजा, खानसाहिब से अली मोहम्मद मीर, चरार-ए-शरीफ से ताहिद हुसैन और राजौरी से विबोध गुप्ता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं, कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सोमवार को 6 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की। इसमें जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख तारिक हमीद करी को सेंट्रल शालटेंग सीट से मैदान में उतारा गया है। यह सूची कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के तुरंत



बाद जारी की गई, जिसमें चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया गया। पार्टी यह चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में लड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी, प्रभारी महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल, हमीद करी, जम्मू-कश्मीर स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख सुखजिंदर सिंह रंधावा, सलमान खुशींद सहित अन्य नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में बैठक में शामिल हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने सीट

बंटवारे के फॉर्मूलों को अंतिम रूप दे दिया है और वे क्रमशः 51 और 32 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। माकपा और जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी (जेकेएनपीपी) को 1-1 सीट आवंटित की गई है। पिछले सप्ताह कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। जम्मू-कश्मीर में चुनाव तीन चरणों (18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर) में होंगे जिसके बाद 8 अक्टूबर को मतों की गिनती होगी।

